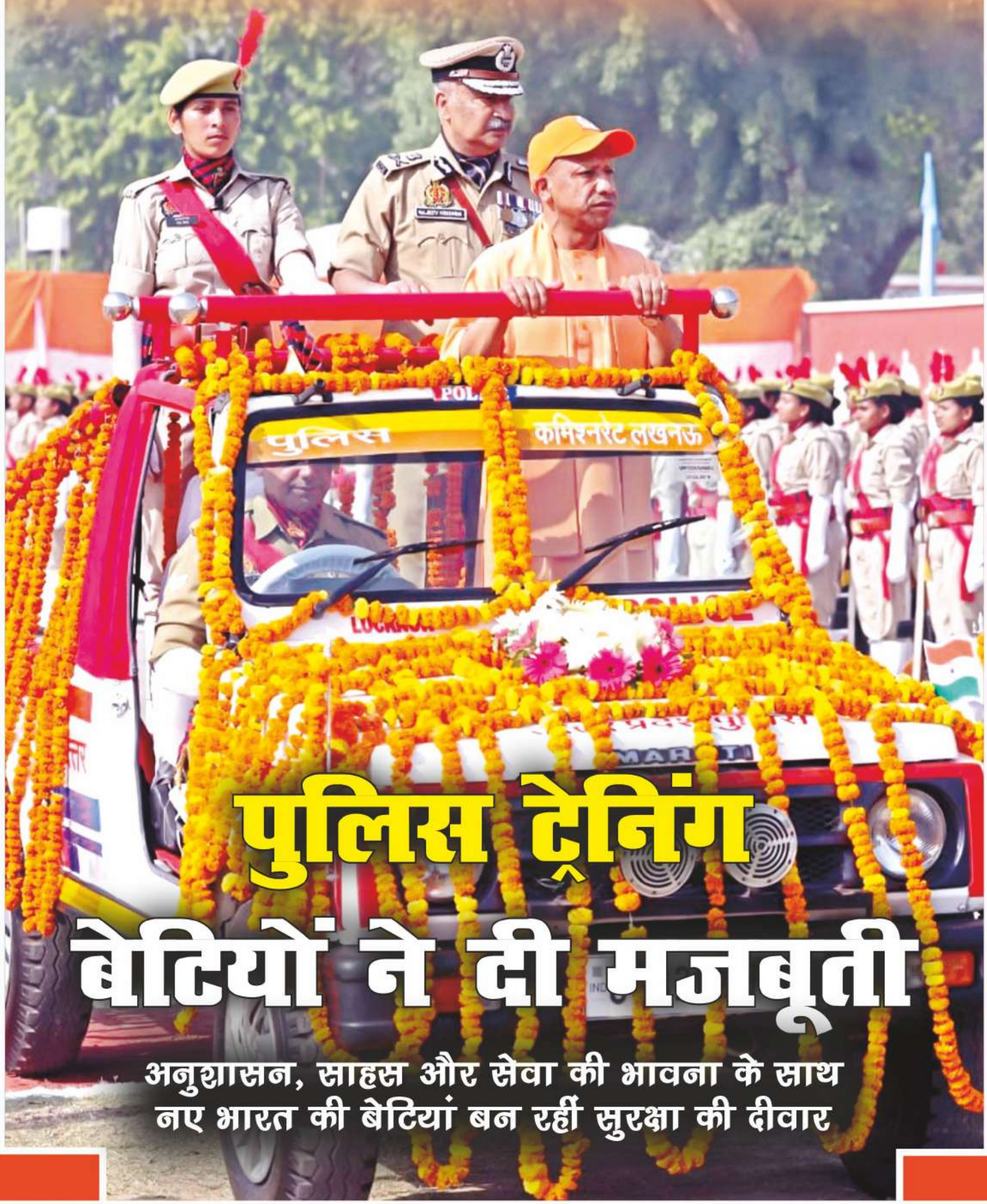
वर्ष : 1 । अंक : 9 । मई 2026 । पृष्ठ : 36 RNI No. UPHIN/25/A0721 मूल्य : 20

हिन्दी मासिक पत्रिका

पॉलिटिकल इमेज



पुलिस ट्रेनिंग

बेटियों ने दी मजबूती

अनुशासन, साहस और सेवा की भावना के साथ
नए भारत की बेटियां बन रहीं सुरक्षा की दीवार

GIC
GURUGRAM INTERNATIONAL CITY

M3M
Our Expertise. Your Joy.

POWERING THE NEXT CHAPTER OF
INDIA'S GROWTH



PRESENTING

M3M
innovation park
AT GURGAON INTERNATIONAL CITY

A WELL CURATED BUSINESS ENVIRONMENT

- Convention & Training Centers
- Business Lounges,Coworking & Incubation Hubs
- Cutting-Edge Utilities
- Wide Internal Roads & Logistics-ready Design
- Thoughtfully Designed Plot Sizes
- EV Charging Stations & Logistics Hubs

1ST EVER INNOVATION PARK WITH A LIFESTYLE OF ITS OWN

LIFESTYLE BEYOND WORK	WELLNESS FACILITIES	RECREATIONAL SPACES	NATURE THEMED PLANNING
			

NOW **LAUNCHING** ▶ **700 - 4,000** sqm **PLOTS** for

DATA CENTERS | **NON-POLLUTING INDUSTRIES** | **BIG BOX RETAIL** | **EV & CLEAN TECH HUBS** | **INCUBATION CENTERS** & MANY MORE

SCAN TO CONNECT

TO RESERVE THIS OPPORTUNITY, **VISIT**
M3M Sales Gallery 77, Sector - 77, Gurugram

8010 111 888 | 8010 334 334

DISCLAIMER: The contents, information, images, visuals or renderings, computer generated images including landscaping on the advertisement are merely representative images or artistic renderings for general informational purposes only, unless specifically stated to be actual photograph. The materials, designs, square footages, fixtures and amenities described by artistic or computer rendering are only for illustration and not necessarily be part of the offer. "Gurugram International City" is an industrial plotted colony, developed and promoted by M3M India Infrastructure Private Limited with Licence no. 149 of 2023 dated 09.09.2023. M3M India is duly registered with Haryana Real Estate Regulatory Authority, vide Regn. No. HRERA-PKL-KNL-[illegible] dated 18.10.2023. All details of the said registered project are available on www.haryanarera.gov.in and may be verified before by the relevant customers at their own independent discretion. Nothing contained herein shall constitute legal offer and does not form part of any legally binding agreement and/or any commitment of any nature. Representations are advised to exercise their independent discretion in relying on the information shown/provided and shall verify all details regarding area, pricing(s), terms of services, payment terms, scheme, calculation terms, offers and payment and price mentioned herein independently with the authorized office/ Promoter company and take appropriate advice prior to concluding any decision for buying any unit(s) in the Project(s) and shall control the same with the office of the Promoter company. **Taxes and statutory charges are extra as per applicable norms. 1 Hotel + 1 of Fitness, 1 Kiosk + 1000 sq. yds. or 4000.89 sq. mtrs., 1 sq. mtr. = 10.764 sq.ft. The use of word "M3M" shall in no manner be construed or interpreted as M3M India Pvt. Ltd. being the Promoter and / or Developer of the Project. Dispute with regard to the interpretation of information or arising from use or reliance of this website will be subject to the exclusive jurisdiction of District Courts at Gurugram, Haryana and Hon'ble High Court of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. All disputes shall be governed by prevailing laws in India.

पॉलिटिकल इमेज

वर्ष : 1 । अंक : 9 । मई 2026 । पृष्ठ : 36

संपादक
गरिमा सिंह

स्वामी, प्रकाशक गरिमा सिंह एवं मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस 41/381 नरही, लखनऊ, ऊ.प्र.-226001 से मुद्रित व सी- 62, इन्दिरा नगर, लखनऊ, ऊ.प्र.-226016 से प्रकाशित।

सम्पादक - गरिमा सिंह

RNI No. UPHIN/25/A0721

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।

e-mail
singsgarima@gmail.com

Phone : 8595476939



28

सड़कों पर उतरा...

इस अंक में



महिला सशक्तिकरण के लिए... 08



10 क्षेत्रीय दलों का अंत...



रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन.. 18

संपादक की कलम से...

परिवर्तन से जीत सकती हैं, महिलाएं



गरिमा सिंह
सम्पादक

महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी, तो वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। वे जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। इसके साथ ही वे उपभोग के पैटर्न में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। खाद्य, ऊर्जा और अन्य संसाधनों के उपयोग के संबंध में वे अधिक समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने में सक्षम होंगी। महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए कि वे सुरक्षित रह सकें-यह वाक्य हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं जो महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने के लिए पर्याप्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की ओर संकेत करते हैं। जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो यह केवल सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि उस व्यापक वातावरण से भी जुड़ जाता है जिसमें हम सभी रहते हैं। वातावरण हमारे चारों ओर का वह परिवेश है जिसमें सभी जैविक और अजैविक तत्व शामिल हैं। यह वही बाहरी घेरा है जो हमारे जीवन, व्यवहार और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसे अक्सर पर्यावरण भी कहा जाता है। आज यह वातावरण संतुलित नहीं रह गया है। तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो रही है। इसका खामियाजा भी भेदभाव से भरा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जेंडर-न्यूट्रल नहीं है। यानी इसके नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर सबसे अधिक पड़ते हैं। कई मायनों में जलवायु परिवर्तन मानवीय अधिकारों को भी पीछे धकेल देता है।

जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ में महिलाओं की मृत्यु अधिक होती है क्योंकि उन्हें जिन्दा रहने के कौशलों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को खेल-कूद से दूर रखा जाता है। महिलाओं के खानपान का कम ख्याल रखा जाता है जिसके चलते भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हमेशा होती है। परिवारों में वे आखिर में खाना खाती हैं। इस तरह की सामाजिक संरचनाएँ संकट के समय में उनकी स्थिति को और कमजोर बना देती हैं। स्पष्ट है, जलवायु परिवर्तन की मार महिलाओं पर अधिक पड़ रही है। गर्मी, सूखा, तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं की वजह से महिलाओं को ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। 1991 में बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान में मरने वालों में लगभग 91 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसका एक कारण यह भी था कि उनमें से बहुत सी महिलाएं तैरना नहीं जानती थीं। तैरना इसलिए नहीं जानती थीं, क्योंकि वे घर के भीतर ही रहती थीं और अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। इसी तरह 2003 में यूरोप में जब भीषण हीट-वेव आई, मरने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। महिलाओं की मृत्यु-दर पुरुषों की तुलना में डीहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण लगभग 15-20 प्रतिशत अधिक थी। जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं पर हिंसा भी बढ़ती है। कई द्वीपीय देशों में चक्रवाती तूफानों के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई है। कई स्थानों पर अस्थायी राहत शिविरों में भी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में मौसम के चलते फसल खराब होने के बाद परिवारों द्वारा लड़कियों को बेचकर मवेशी खरीदने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। दक्षिण केन्या में श्फिश फॉर सेक्सश जैसी प्रथा का उल्लेख मिलता है, जहां मछली के बदले लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है।

एक स्वीडिश अध्ययन के अनुसार पुरुष औसतन केवल दो प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन के लिए वे लगभग 16 प्रतिशत अधिक जिम्मेदार होते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष अधिक बाहर निकलते हैं और पेट्रोल-डीजल का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के चलते और गहरी होती लैंगिक असमानता को समझना जरूरी है। उड़ीसा में आए एक साइक्लोन की केस-स्टडी में सामने आया कि प्राकृतिक आपदा के बाद आर्थिक संकट के कारण एक परिवार ने अपनी बेटी को नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसे बांग्लादेश में बेच दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइक्लोन के कारण उनकी कृषि भूमि लगभग 10 साल के लिए उपज के लायक नहीं बची थी। वहीं महाराष्ट्र में वॉटर वाइफ यानी पानी-बाई देखने मिलती हैं, जिसमें पानी भरने के लिए पुरुष कई महिलाओं से विवाह करते हैं। यह जलवायु संकट से जुड़ा एक सामाजिक और लैंगिक अन्याय है।

भगवान परशुराम सदियों से धर्म और न्याय के प्रतीकः डॉ धर्मेन्द्र सिंह

परशुराम जी को अमर माना जाता है मान्यता के अनुसार वह आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं और जरूरत पड़ने पर अत्याचारियों का विनाश करने के लिए प्रकट हो जाते हैं उनके अमरत्व और धर्म रक्षा की विशेषता उन्हें अन्य अवतारों से अलग बनाती है भगवान परशुराम जी के कार्य समाज तथा मानवता के लिए प्रेरक है उन्होंने अन्यायी और अत्याचारी लोगों से समाज को मुक्ति दिला कर धर्म की स्थापना की।



डॉ धर्मेन्द्र सिंह

हिंदू धर्म में छठवे अवतार भगवान परशुराम सदियों से धर्म और न्याय के प्रतीक बने हुए हैं। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। पिता महर्षि यांदग्नि और मां रेणुका धर्म परायण थे। भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा तो हुए परंतु उनका स्वभाव और कर्म योद्धा जैसा था उनका नाम परशुराम दो शब्दों परशु (फरसा) और राम से बना है। कहा जाता है कि फरसा उन्हें भगवान शंकर ने प्रदान किया था वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में परीपूर्ण थे उनके व्यक्तित्व में ज्ञान और साहस का अद्भुत समावेश था । परशुराम जी का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से अत्याचारियों का विनाश करना था उनके समय में कई राजा अत्याचारी अहंकारी और अन्यायी बन गए थे जो कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आम जनता को कष्ट पहुंचाने लगे थे ।

सनातन धर्म ग्रंथो के अनुसार परशुराम जी ने अत्याचारी राजाओं का संहार करके धर्म की स्थापना की थी जिससे समाज में न्याय और शांति कायम हुई परशुराम जी केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान शिक्षक थे । महाभारत काल के भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण उनके शिष्य थे जो आज भी इतिहास में अपनी वीरता के कारण अमर हैं । अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है इस दिन अच्छे कार्य करने की विशेष मान्यता है। अक्षय तृतीया को त्रेता युग आरंभ हुआ था यह युग आरंभ की तिथि होने के कारण अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है ।

यही कारण है कि इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त की मान्यता प्राप्त है। एक बार देव गुरु बृहस्पति के परामर्श से देवराज इंद्र विधि विधान से अक्षय तृतीया व्रत रखकर सभी पापों से मुक्त हुए थे एक अन्य कथा के अनुसार धर्मदास नामक एक वैश्य अक्षय तृतीया व्रत को निर्धन होकर भी संपन्न किया था परिणाम स्वरुप मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में राजा हुआ। परशुराम जी को अमर माना जाता है मान्यता के अनुसार वह आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं और जरूरत पड़ने पर अत्याचारियों का विनाश करने के लिए प्रकट हो जाते हैं उनके अमरत्व और धर्म रक्षा की विशेषता उन्हें अन्य अवतारों से अलग बनाती है भगवान परशुराम जी के कार्य समाज तथा मानवता के लिए प्रेरक है उन्होंने अन्यायी और अत्याचारी लोगों से समाज को मुक्ति दिला कर धर्म की स्थापना की। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि,शक्ति ज्ञान और कौशल का प्रयोग हमेशा धर्म और समाज की भलाई के लिए होना चाहिए।




पुलिस
कमिश्नरेट लखनऊ



बेटियों ने पुलिस ट्रेनिंग में दिया मजबूती, तत्परता, समर्पण व अनुशासन का परिचय: सीएम योगी

अभी जितना पसीना बहेगा, बाद में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी : मुख्यमंत्री

₹60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती: 2025 बैच के पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षी प्रशिक्षण के दौरान बेटियों ने जिस मजबूती, तत्परता, समर्पण व अनुशासन का परिचय दिया है, वह सराहनीय है। अनुशासन व टीमवर्क का उत्कृष्ट भाव सबसे बड़ी ताकत है। इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की भावना वर्दीधारी बल का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है।

सीएम योगी रविवार को 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के अंतर्गत वर्ष 2025 बैच के पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। रिजर्व पुलिस लाइन में हुए आयोजन में सीएम ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली।

कानून अपराधी के लिए कठोर और नागरिकों के लिए संवेदनशील होना चाहिए

सीएम ने प्रशिक्षण पूर्ण कर दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने वाली महिला आरक्षियों को बधाई दी और कहा कि सभी ने लगन व अनुशासन के साथ कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब आप सबको जनपदों की फील्ड ड्यूटी में जाना है। याद रखिए, कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी आरक्षी प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल व मूल्यों का उपयोग करते हुए निष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्य परायणता से यूपी पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।

कई प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर देखा,अब बेहतर प्रशिक्षण व सुविधाएं

सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश के 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियनों, 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों में एक साथ आरक्षी दीक्षांत परेड आयोजित की जा रही है। 15 जून 2025 को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। 21 जुलाई से इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस दौरान मैं भी विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में गया और देखा कि प्रशिक्षण व सुविधाएं पहले से बेहतर हुई है।

हमने यूपी को देश के बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी पुलिस के सामने चुनौती व संकट था, लेकिन हमने इसे देश के बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। हमने 2.18 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती और 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों का प्रमोशन किया। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता महज 3 हजार थी, लेकिन हमने



60244 पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण यूपी के केंद्रों में ही एक साथ संपन्न किया है, जो 9 वर्ष में अर्जित की गई प्रगति को दर्शाता है।

2017 में टूटे-फूटे बैरक थे, अब 55 जनपदों में हाईराइज भवन

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले पुलिस के बैरक टूटे-फूटे, खपड़ैल व टीनशेड के होते थे, लेकिन अब 55 जनपदों में पुलिस कार्मिकों के बैरक व आवासीय सुविधा के हाईराइज भवन दिखाई देते हैं। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। हर प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया। यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल भी लांच किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक व आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया। आउटडोर प्रशिक्षण में पुरानी 303 नॉट राइफल के स्थान पर आधुनिक इंसास व एसएलआर राइफल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

मिशन कर्मयोगी में यूपी का उत्कृष्ट प्रदर्शन

सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। हाल में संचालित साधना सप्ताह में शासकीय कर्मचारियों ने 1.25 करोड़ कोर्स पूर्ण कर यूपी को देश में पहला स्थान दिलवाया है। यूपी पुलिस ने इसमें 28 लाख कोर्स पूरे किए। यूपी पुलिस देश भर के सभी राज्यों-विभागों में चौथे स्थान पर रही है।

यूपी एटीएस को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप दिया जा रहा प्रशिक्षण

सीएम योगी ने कहा कि यूपी एटीएस के अधिकारियों व जवानों को एनआईए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है। पुलिस बल को व्यावहारिक दक्षता व सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की गई है। यहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अब अपराधियों में भय, पुलिस का मनोबल ऊंचा

सीएम योगी ने कहा कि यूपी पुलिस देश में मॉडल व 'स्मार्ट' है। यूपी पुलिस आमजन को सुरक्षा, सुविधा उपलब्ध कराने में योगदान दे रही है। अब यूपी में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर कोई राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स व अवैध वसूली भी नहीं होती। अब यूपी में अपराधियों के मन में भय और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले प्रदेश की छवि अराजकता-अस्थिरता का पर्याय बनी था, लेकिन अब स्पष्ट नीति व साफ नीयत का परिणाम साफ दिखाई देता है। 2017 के पहले की स्थिति बयां करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में दंगे और महीनों कर्फ्यू लगता था। कोई खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता था, लेकिन यूपी पुलिस अब दंगे से पहले ही उसे रोकने में सफल है। अब यूपी में महिला कार्यबल 13 से बढ़कर 36 फीसदी से अधिक हुआ है। यूपी पुलिस ने खुद को आर्थिक प्रगति की रीढ़ के रूप में भी तैयार किया है। इस कारण प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है।

2019-20 से चल रहा 'मिशन शक्ति'

सीएम योगी ने कहा कि 2019-20 से अनवरत मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। तीन महिला पीएसी बटालियनों (लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई कोरी व बदायूं में अवंती बाई लोधी) का गठन किया गया है। तीन अन्य नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। 17 नगर निगम व गौतमबुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजना को लागू किया है।

यूपी पुलिस की बेहतरी के लिए लगातार कार्य

सीएम योगी ने कहा कि यूपी को 'लॉ एंड ऑर्डर' का आदर्श मॉडल बनाने और अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई। इनमें अनिवार्य रूप से 20 प्रतिशत बेटियों को भर्ती किया गया है। हमारी सरकार ने 2017 की तुलना में यूपी पुलिस के बजट को तीन गुना से अधिक बढ़ाया और 7 पुलिस कमिश्नरेट भी स्थापित किए। यूपी एसएसएफ (स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स) का गठन किया गया। पिंक पुलिस बूथों की स्थापना हुई। एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक, साइबर एक्सपर्ट, आधुनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित किया गया। 12 फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई, 6 लैब निर्माणाधीन हैं। हर जनपद में दो-दो मोबाइल फॉरेंसिक लैब स्थापित की गईं। हमने यूपी-112 के रिस्पांस टाइम को 65 मिनट से घटाकर 6-7 मिनट लाने में सफलता हासिल की है।

योगी सरकार का बड़ा अभियान, हर कार्यस्थल बनेगा महिलाओं के लिए सुरक्षित

- नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की नई नींव रख रही है योगी सरकार की मुहिम
- प्रत्येक जिले में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएंगे 'पॉश' से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पॉश' अधिनियम के अलावा कामकाजी महिलाओं के वित्तीय और कानूनी अधिकारों पर भी हो रही चर्चा
- पॉश' अधिनियम पर जागरूकता खोलेगी महिलाओं के अधिकारों की नई राह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान ने प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ('पॉश' एक्ट) के प्रावधानों के प्रति प्रतिभागियों और आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

अधिकारी, कर्मचारी, छात्राएं बन रहीं अभियान का हिस्सा: जागरूकता अभियान में सरकारी-निजी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य, कॉलेज छात्राएं, अधिवक्ता, श्रमिक संगठन और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तीकरण मुहिम का हिस्सा यह अभियान कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 (पॉश) और कामकाजी महिलाओं के वित्तीय-कानूनी अधिकारों पर केंद्रित है, जो नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में नया आयाम जोड़ रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना उद्देश्य

अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत 'पॉश' अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। अधिनियम कार्यस्थल पर शारीरिक, मौखिक या गैरमौखिक आचरण को, जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में परिभाषित करता है। दस से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय समिति शिकायतों की सुनवाई करती है। शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा तीन महीने है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। यह अधिनियम महिला की गोपनीयता की रक्षा करता है और दोष सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या जुर्माना करने का नियोक्ता को अधिकार है। नियोक्ता का दायित्व है कि कार्यस्थल सुरक्षित बने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हों और समिति की सिफारिशों का पालन हो।

महिलाओं के वित्तीय और कानूनी अधिकारों पर दिया गया जोर

अभियान में 'पॉश' अधिनियम के अलावा कामकाजी महिलाओं के वित्तीय और कानूनी अधिकारों पर भी चर्चा की जा रही है। मातृत्व अवकाश के लाभ, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य-सुरक्षा प्रावधान, श्रमिक कानूनों के तहत विशेष सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग और बीमा योजनाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक सशक्तीकरण ही वास्तविक महिला सुरक्षा का आधार है।





धुर विरोधियों ने 'शत्रुता' के बजाय 'शिष्टता' को चुना

● सदन में नेताजी (मुलायम सिंह) हमेशा भाजपा की नीतियों पर तीखे प्रहार करते थे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में दोनों के बीच गहरी आत्मीयता थी। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वे अक्सर लखनऊ आने पर अटल जी से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर जाया करते थे। यही नहीं, संसद के पटल पर धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव ने अपने अंतिम संसदीय भाषणों में से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरेआम कामना की थी।

निदा फ़ाज़ली साहब की यह पंक्तियाँ केवल शायरी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय संसदीय लोकतंत्र का वह अघोषित आचरण सूत्र है जिसे आज के दौर में अक्सर बिसरा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की ठेठ राजनीतिक और व्यावहारिक भाषा में कहें तो—रसियासत में दुश्मनी उतनी ही की जानी चाहिए कि कल को जब सार्वजनिक जीवन में गले मिलना पड़े, तो कम से कम आँखें मिलाने में शर्म न आए।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के राजभवन से सामने आई एक तस्वीर ने इसी शाश्वत सिद्धांत को एक बार फिर देश के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह तस्वीर थी जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गाजीपुर के समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी की। सोशल मीडिया के इस दौर में, जहाँ राजनीतिक विमर्श का स्तर लगातार गिर रहा है और 'कट्टरता' को ही निष्ठा का एकमात्र पैमाना मान लिया गया है, वहाँ इस मुलाकात ने आम जनता और विश्लेषकों दोनों को चौंकाया। चौंकना



स्वाभाविक भी था, क्योंकि ये दोनों नाम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की उस धरती से आते हैं जहाँ का राजनीतिक इतिहास हमेशा से बेहद तीखा, आक्रामक और ध्रुवीकृत रहा है। चुनावी रणक्षेत्र में एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे इन दो चेहरों को जब राजभवन में बेहद आत्मीयता, सम्मान और शिष्टाचार के साथ एक-दूसरे का सत्कार करते देखा गया, तो ट्रोल सेना और अंध-समर्थकों के खेमे में सन्नाटा पसर गया। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस मुलाकात में कुछ भी अप्रत्याशित या गलत था? उत्तर है—बिल्कुल नहीं। यह मुलाकात यूपी की उस समृद्ध राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है जो मतभेदों के बीच भी मर्यादा की कद्र करना जानती है।



#गाजीपुर की राजनीतिक विरासत और यह मुलाकात

गाजीपुर की राजनीतिक चेतना हमेशा से प्रखर और अपनी अलग पहचान रखने वाली रही है। यह वही धरती है जिसने 1962 में संसद को विश्वनाथ सिंह गहमरी जैसा सांसद दिया, जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भुखमरी और गरीबी का ऐसा मर्मस्पर्शी खाका संसद के पटल पर खींचा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आँखें नम हो गई थीं और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 'पटेल आयोग' का गठन किया था। इसी धरती से



कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रखर नेता सरजू पांडेय भी आते थे, जिनकी वैचारिक लड़ाइयाँ कड़क थीं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा शालीन रहा।

मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी का चुनावी इतिहास भी इसी प्रखर वैचारिक द्वंद्व का हिस्सा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को परास्त किया था। राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच की खाइयाँ बहुत गहरी रही हैं। इसके बावजूद, जब संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति आधिकारिक दौरे पर जम्मू-कश्मीर पहुँची, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समिति के सदस्य के रूप में आए अफजाल अंसारी का उसी गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसा अन्य सदस्यों का किया। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारत में 'संवैधानिक दायित्व' और 'व्यक्तिगत शिष्टाचार' हमेशा दलीय राजनीति से ऊपर स्थान पाते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति के कुछ 'क्लासिक' तथ्य और उदाहरण

उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का 'पावरहाउस' कहा जाता है। यहाँ जितनी तीखी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उतने ही शानदार उदाहरण व्यक्तिगत सम्मान और शिष्टाचार के भी मिलते हैं:

चंद्रभानु गुप्ता और चरण सिंह: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता और चौधरी चरण सिंह के बीच के राजनीतिक और वैचारिक मतभेद जगजाहिर थे। दोनों कांग्रेस के भीतर और बाद में बाहर भी एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे। लेकिन जब चंद्रभानु गुप्ता का स्वास्थ्य खराब हुआ या जब कभी वे व्यक्तिगत संकट में थे, तो चौधरी चरण सिंह हमेशा उनके पास जाते थे और दोनों पुराने साथियों की तरह घंटों बातें करते थे।

मुलायम सिंह यादव और अटल बिहारी वाजपेयी: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच का रिश्ता अद्भुत था। सदन में नेताजी (मुलायम सिंह) हमेशा भाजपा की नीतियों पर तीखे प्रहार करते थे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में दोनों के बीच गहरी आत्मीयता थी। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वे अक्सर लखनऊ आने पर अटल जी से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर जाया करते थे। यही नहीं, संसद के पटल पर धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव ने अपने अंतिम संसदीय भाषणों में से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरेआम कामना की थी कि वे दोबारा चुनकर आएं।

मायावती और कल्याण सिंह की 'राखी' की राजनीति: 90 के दशक के मध्य की उत्तर प्रदेश की राजनीति को याद करें, जब धुर विरोधी विचारधारा वाली बसपा और भाजपा ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। मायावती ने सार्वजनिक मंच से कल्याण सिंह को 'भाई' कहकर राखी बांधी थी। हालांकि बाद में उनके गठबंधन टूट गए और तीखे आरोप-प्रत्यारोप लगे, लेकिन संकट के समय या सार्वजनिक मंचों पर कभी शिष्टाचार की सीमा नहीं लांघी गई।

* अखिलेश यादव और राजनाथ सिंह: समाजवादी पार्टी और भाजपा के वैचारिक विरोध के बावजूद, जब भी लखनऊ या दिल्ली के सार्वजनिक आयोजनों में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ



सिंह और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमने-सामने आते है, तो अखिलेश यादव हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। यह यूपी की 'तहजीब' और 'मर्यादा' का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

'संसदीय समितियों' की मूक संस्कृति

अक्सर आम जनता टीवी चैनलों पर होने वाले शोर-शराबे, हंगामे और सोशल मीडिया की कटुता को ही राजनीति की वास्तविक कार्यप्रणाली मान बैठती है। जबकि सच इसके विपरीत है। संसद की स्थायी समितियाँ कैमरे की चकाचौंध से दूर बंद कमरों में काम करती हैं। इन समितियों में भाजपा, कांग्रेस, सपा, तृणमूल समेत सभी दलों के सांसद एक साथ बैठते हैं, एक ही मेज पर भोजन करते हैं और देश के गंभीर कानूनों व नीतियों पर दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर आम सहमति बनाते हैं। मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी की मुलाकात इसी 'कमेटी कल्चर' और संसदीय गरिमा का विस्तार थी।

संपादकीय दृष्टिकोण: समर्थकों के लिए एक बड़ी सीख

यह मुलाकात उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं और कट्टर समर्थकों के लिए एक गंभीर आत्मनिरीक्षण का विषय है, जो सोशल मीडिया पर या चौराहों पर अपने पसंदीदा नेताओं के लिए अपनों से संबंध खराब कर लेते हैं। चाणक्य नीति का एक प्रसिद्ध सूत्र है—'राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु।' इतिहास गवाह है कि जो नेता आज एक-दूसरे के खिलाफ विषवमन कर रहे होते हैं, वे कल किसी नए गठबंधन के तहत एक ही मंच पर मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे होते हैं।

यूपी की राजनीति ने 1993 का 'सपा-बसपा' गठबंधन भी देखा है, 2017 का 'यूपी के लड़के' (सपा-कांग्रेस) गठबंधन भी देखा है और 2019 का 'सपा-बसपा' का दोबारा हुआ ऐतिहासिक प्रयोग भी देखा है। जो कार्यकर्ता कल तक एक-दूसरे के खिलाफ सड़कों पर लड़ रहे थे, उन्हें अपने नेताओं के आदेश पर अचानक एक-दूसरे के लिए वोट मांगना पड़ा।

सियासत की बिसात पर मोहरे चाहे जितनी आक्रामकता से चले जाएं, खेल समाप्त होने के बाद राजा, वजीर और प्यादे एक ही डिब्बे में सहेज कर रख दिए जाते हैं। जनता को यह समझना होगा कि विरोध नीतियों और विचारधारा का होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं। जब तक भारतीय लोकतंत्र में धुर विरोधी नेता भी एक-दूसरे को सम्मान देने की यह संवैधानिक और मानवीय मर्यादा बनाए रखेंगे, तब तक इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा अक्षुण्ण रहेगा। राजभवन की यह तस्वीर किसी समझौते की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तहजीब और इसकी जीवंतता की एक खूबसूरत और अनुकरणीय बानगी है।

गंगौली से राजभवन तक

सरजू पांडेय और राही मासूम रज़ा की वो 'गंगा-जमुनी' तहजीबजब हम गाजीपुर की राजनीति की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल लट्ठ और बारूद की जमीन नहीं है, बल्कि यह प्रखर वैचारिक और साहित्यिक चेतना की उर्वर भूमि है। गाजीपुर का इतिहास गवाह है कि यहाँ चुनावी मुकाबले जितने तीखे हुए, व्यक्तिगत संबंध और मर्यादाएं उतनी ही मजबूत रहीं।कामरेड सरजू पांडेय और विरोधियों का सत्कार:गाजीपुर की राजनीति में कम्युनिस्ट नेता कामरेड सरजू पांडेय एक किंवदंती की तरह हैं। वे कई बार गाजीपुर और रसड़ा से सांसद व विधायक रहे। संसद में वे कांग्रेस और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के सबसे तीखे और प्रखर आलोचक माने जाते थे। उनके भाषणों में व्यवस्था के प्रति तीखा आक्रोश होता था। लेकिन गाजीपुर के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि चुनाव खत्म होते ही सरजू पांडेय अपने वैचारिक विरोधियों के घर जाकर चाय पीते थे और सुख-दुख साझा करते थे। चुनावी रंजिश को उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत आचरण पर हावी नहीं होने दिया।डॉ. राही मासूम रज़ा और 'आधा गाँव' का दर्शन:गाजीपुर के गंगौली गाँव की पृष्ठभूमि पर कालजयी उपन्यास 'आधा गाँव' लिखने वाले प्रख्यात साहित्यकार और महाभारत धारावाहिक के संवाद लेखक डॉ. राही मासूम रज़ा ने इसी मिट्टी की तासीर को बयां किया था। राही साहब खुद गाजीपुर की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत के सबसे बड़े पैरोकार थे। वे कहते थे कि गाजीपुर के लोगों के खून में एक अजीब सा फक्कड़पन और अलहड़पन है; यहाँ लोग मुद्दों पर जी-जान से लड़ते हैं, लेकिन जब बात मर्यादा और सत्कार की आती है, तो वे अपनी पूरी तहजीब बिछा देते हैं।इस ऐतिहासिक संदर्भ का आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वमनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी की यह मुलाकात इसी गाजीपुरिया फक्कड़पन और संसदीय शिष्टाचार का आधुनिक संस्करण है। भले ही पिछले तीन दशकों में गाजीपुर की राजनीति में बाहुबल और ध्रुवीकरण का रंग गहरा हुआ हो, लेकिन इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि बुनियादी संस्कार आज भी जीवित हैं।जब अफजाल अंसारी राजभवन पहुँचे, तो उन्होंने गाजीपुर की उसी 'संसदीय मर्यादा' को आगे बढ़ाया, और जब मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया, तो उन्होंने राजभवन की गरिमा के साथ-साथ गाजीपुर की 'अतिथि देवो भव' की परंपरा को भी जीवित रखा। यह मुलाकात चीख-चीख कर कहती है कि चुनावी हार-जीत और राजनैतिक शत्रुता अपनी जगह है, लेकिन जब दो जनप्रतिनिधि मिलते हैं, तो वे अपनी मिट्टी की लाज रखना जानते हैं।



90 प्रतिशत सरकारी सहायता से संचालित परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर

प्रदेश में संचालित 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

सीएफसी परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान और 10 प्रतिशत उद्यमियों का योगदान







प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों, हस्तशिल्प, बुनकरी और सूक्ष्म उद्यमों को नई मजबूती देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार की मंशा है कि ओडीओपी योजना के तहत स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) केवल सीमित लोगों तक न रहकर अधिक से अधिक कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं से जोड़ें। इसी उद्देश्य से मंगलवार को प्रदेश में संचालित 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सीएफसी में सीमित लाभार्थियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ केवल कुछ सदस्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से सीएफसी परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान और 10 प्रतिशत उद्यमियों का योगदान रखा गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन, परीक्षण, स्किल ट्रेनिंग और कॉमन टूल्स जैसी सुविधाएं सुलभ हो सकें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए मोबाइल संदेश, पम्पलेट, उद्योग बंधु बैठकों और मीडिया माध्यमों का उपयोग करने को कहा गया। साथ ही सभी सीएफसी में "सिटीजन चार्टर" प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को उपलब्ध सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। बैठक में अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, वाराणसी, खुर्जा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या और गाजियाबाद सहित विभिन्न जिलों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर बुनकर सीएफसी में लगभग 4 करोड़ रुपये की सहायता से स्थापित परियोजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक बुनकर आधुनिक सुविधाओं से जुड़ सकें। वहीं बनारस के सिल्क उत्पाद सीएफसी में लगभग 9 करोड़ रुपये की सहायता से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक स्तर पर कारीगरों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में बुनकरों और कारीगरों ने बिजली, धागे की लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा और तकनीकी उन्नयन से जुड़े मुद्दे भी रखे।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि योगी सरकार ने बुनकरों को राहत देने के लिए वर्षों तक फ्लैट रेट विद्युत योजना लागू रखी, जिसके तहत 2006 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 44 करोड़ रुपये का विद्युत व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया। सरकार की प्राथमिकता है कि पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से जुड़े लोग आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। गाजियाबाद के इंजीनियरिंग एवं टूल रूम आधारित सीएफसी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वहां सीएनसी मशीन, 3डी प्रिंटिंग, मटेरियल टेस्टिंग और स्किल ट्रेनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और रक्षा क्षेत्र के लिए कंपोनेंट निर्माण की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।

मुरादाबाद के फिजिकल वेपर डिपोजिशन (पीवीडी) प्लांट को पर्यावरण अनुकूल तकनीक



का उदाहरण बताते हुए उसकी कार्यक्षमता को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वहीं संभल के बटन उद्योग सीएफसी में 70 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग को सकारात्मक संकेत बताते हुए कच्चे माल और बिजली उपलब्धता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। खुर्जा ब्लैक पॉटरी सीएफसी को बैठक में सफलता की मिसाल बताया गया। इस परियोजना से 1253 से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं और कारोबार 15-20 लाख रुपये से बढ़कर 90-95 लाख रुपये तक पहुंचा है। इसे पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया। कारीगरों द्वारा मिट्टी भंडारण के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग भी बैठक में रखी गई।

सहारनपुर वुड क्राफ्ट, आगरा लेदर क्लस्टर, बरेली और मेरठ के गुड़ प्रसंस्करण सीएफसी की भी समीक्षा की गई। मेरठ परियोजना में 1800 किसानों को जोड़कर मूल्य संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उद्योग बंधु बैठकों का आयोजन सीएफसी परिसरों में किया जाए और बड़ी उद्योग इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर छोटे उद्यमों को बड़े बाजार और सप्लाई चेन से जोड़ा जाए।



नगर निगम के पार्षद से लेकर भारत सरकार में वित्त मंत्री और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंकज चौधरी ऐसा नाम बन गया है जो नगर निगम के पार्षद से लेकर भारत सरकार में वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में प्रदेश अध्यक्ष की सफर अपने आप में एक अनोखा उदाहरण ही मानी जाएगा। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में पैदा हुए पले बढ़े पंकज चौधरी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद नगर निगम में पार्षद चुने गए और उसी सत्र में डिप्टी मेयर की सफर तय की। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया उन दिनों गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की तूती बोलती थी एक सामान्य राजनीतिक परिवार में जन्मे पंकज चौधरी ने इन दोनों महानुभावों को पीछे छोड़ते हुए संसद का चुनाव जीत कर दिल्ली का सफर तय किया उसके बाद से फिर पंकज ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सात बार के सांसद पंकज चौधरी से मिलने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को यह एहसास ही नहीं होता कि मैं सात बार के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहा हूं।

अध्यक्ष का दायित्व संभालते ही पंकज चौधरी ने आम कार्यकर्ताओं के लिए अपना दरवाजा खोल दिया और आम हो या खास सबसे मिलकर उनकी बातों को सुनने का ज्यादा प्रयास किया यही कारण है कि बहुत अल्प समय में ही पंकज चौधरी ने पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भू भाग में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो चुके हैं और अब तो बहुत से लोगों को नाम से भी बुलाने लगे हैं जो उनके असाधारण व्यक्तित्व को दर्शाता है। लखनऊ में पंकज चौधरी ने जब जब अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया तो उन्होंने भाजपा के बड़े पदाधिकारीयो के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी और छोटे से छोटे पदाधिकारी को भी अपना दरवाजा खोलकर उन्हें गृह प्रवेश के भोज में आने के लिए आमंत्रित कर कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का कार्य किया है कि हम कार्यकर्ता से ही यहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हम हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ है जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के जुबान पर उनके राजधानी वाले मकान में गृह प्रवेश की चर्चा सहज ही सुनने को मिल रही है रही बात उनके राजनीतिक कौशल की 1995 प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और पूरे प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी का एक जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था जो महाराजगंज से पंकज चौधरी के संसदीय क्षेत्र से। चौधरी साहब कभी भी संगठन का दायित्व भले नहीं संभाले हैं लेकिन उनके अंदर संगठन शिल्पी



के वे सारे गुण कूट कूट के भरे हुए हैं जो एक सधे और सुलझे राजनेता में पाए जाते हैं। प्रदेश के मुखिया के तौर पर चौधरी साहब का भरपूर प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं तक पहुंचे जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि अंबेडकर नगर जैसे भाजपा के लिए चुनावी दृष्टिकोण से ऊसर बंजर जनपद में भी आकर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनकर संगठन की बैठक कर और पुराने जनसंघ कालीन नेता प्रथम जिला अध्यक्ष डॉ राजित राम त्रिपाठी जी के आवास पर जाकर उनका हाल चाल लेकर राजनीति में आगे ना बढ़ पाने वाले कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का कार्य किया कि पंकज के रहते निराश होने की जरूरत नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी में चौधरी साहब के पहले भी प्रदेश अध्यक्ष हुए लेकिन चौधरी साहब की खासियत यह है कि जिन भी क्षेत्रों में जाते हैं वहां के पुराने नेताओं से मिलने का भरपूर प्रयास करते हैं जिससे नेतायो और कार्यकर्ताओं में उत्साह और उर्जा का संचार तो होता ही है जो किन्ही कारणों से घर बैठ गए होते हैं केवल विचारधारा के कारण पार्टी से जुड़े होते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में सक्रिय होने का जोश भर देते हैं।

भारत सरकार में मंत्री होने के कारण अध्यक्ष जी को दिल्ली की भी यात्रा करनी पड़ती है उनका कार्यालय सही रूप से संचालित होता रहे इसके लिए उन्होंने ओम प्रकाश पटेल जैसे एक सुलझे हुए व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर यह सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी बड़े पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई होती तो गोलबंदी अथवा किसी कार्यकर्ता से नाराजगी के कारण उसकी उपेक्षा होने की गुंजाइश होती यही कारण है कि एक निर्विवाद व्यक्ति को वहां बैठकर उन्होंने यह संदेश देने का कार्य किया है की आम हो या खास किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की योग्यता पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा।

2027 के चुनावी दंगल में यूपी को भगवामय करने की जिस अपेक्षा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंकज चौधरी पर दांव लगाया है वह उनके अब तक की मेहनत और कार्ययोजनायो से यह सिद्ध कर रही है कि नेतृत्व के कसौटी पर पंकज जी खरे उतरते हुए तीसरी बार प्रदेश में भगवा लहराने में सफल होंगे। अंतोगत्वा हम कह सकते हैं कि कर्म योगी पंकज चौधरी का सार्वजनिक जीवन नगर निगम से भारत सरकार में वित्त मंत्री तक का सफर जीवन संघर्ष संगठन निष्ठा और निरंतर जन सेवा का प्रतिफल है।



उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में सत्र 2026-27 के लिए स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, फतेहपुर और सहारनपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा 6, 9 और 11 की कुल 518 संभावित रिक्त सीटों पर प्रवेश होगा।



आवेदन के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित

दरअसल प्रदेश को सहारनपुर और फतेहपुर में दो नए स्पोर्ट्स कॉलेज मिल गए हैं। यहां सत्र 2026-27 से एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस तरह प्रदेश में कुल 5 स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया चालू है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए खेल साथी पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। अभ्यर्थी स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की वेबसाइट SPORTSCOLLEGELKO.IN या खेल साथी पोर्टल https://khelsathi.in पर जाकर आवेदन कर रहे हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है।

एडमिशन के लिए पीईएन नंबर हुआ अनिवार्य

योगी सरकार ने इस बार आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए यूडाइस पोर्टल से जारी पर्मानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन) को अनिवार्य कर दिया है। इस बार बिना पर्मानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन) के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड का सत्यापन यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। योगी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इन पांचों स्पोर्ट्स कॉलेजों में अलग-अलग खेलों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ के गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल जैसे खेल संचालित होंगे।

सहारनपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में भारोत्तोलन के लिए दाखिले

गोरखपुर के बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में वॉलीबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, हॉकी और जूडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। जबकि इटावा (सैफई) के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी और तैराकी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फतेहपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में केवल कक्षा 9 के लिए एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल और कुश्ती में प्रवेश होगा। सहारनपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में भी केवल कक्षा 9 के लिए एथलेटिक्स, हॉकी, बॉक्सिंग, जूडो और भारोत्तोलन में दाखिले किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उनके पसंदीदा खेल में बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

इन अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के साथ अपनी स्थिति करनी होगी स्पष्ट

प्रवेश के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक पात्रताएं भी तय की हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का सत्र 2025-26 में कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी प्रकार कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 और कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। जिन छात्रों ने एक वर्ष का गैप लिया है, उन्हें शपथ पत्र के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल लेकिन सुरक्षित बनाया गया है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को अपनी नवीन फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अंकपत्र, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पर्मानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन) नंबर तैयार रखना होगा।

100 अंकों की होगी प्रारंभिक चयन परीक्षा

रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी किए जाएंगे, जिनकी मदद से छात्र आवेदन फार्म भर सकेंगे।

योगी सरकार ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट और प्रदर्शन आधारित रखा है। प्रारंभिक चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 50 अंक फिजिकल टेस्ट और 50 अंक स्किल एवं गेम टेस्ट के होंगे। दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। खेल विशेषज्ञ मैदान पर खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और प्रदर्शन का परीक्षण करेंगे। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी।

प्रवेश के लिए न्यूनतम लंबाई तय की गई

प्रारंभिक चयन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। मुख्य परीक्षा भी 100 अंकों की होगी और इसमें भी फिजिकल व स्किल टेस्ट शामिल रहेंगे।

प्रदेश सरकार ने खेलवार विशेष मानक भी निर्धारित किए हैं। वॉलीबॉल में प्रवेश के लिए न्यूनतम लंबाई तय की गई है। कक्षा 9 में बालकों की लंबाई 175 सेंटीमीटर और बालिकाओं की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि कक्षा 11 के लिए यह सीमा क्रमशः 180 और 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अधिक लंबाई वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी।

अभ्यर्थियों की होगी जैविक आयु जांच

कुश्ती, बॉक्सिंग और जूडो जैसे खेलों के लिए अलग-अलग भार वर्ग भी तय किए गए हैं। एथलेटिक्स में रनिंग, जम्प और थ्रो की विभिन्न स्पर्धाओं में आवेदन किए जा सकेंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की जैविक आयु जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में अलग-अलग खेलों के अनुसार मेडिकल जांच केंद्र बनाए गए हैं। जैविक आयु जांच में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर अंतिम प्रवेश दिया जाएगा। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य अतुल सिन्हा ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह उनकी खेल प्रतिभा, फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देशभर में यूपी के दो शहर टॉप 10 में

- पहले नंबर पर लखनऊ और दसवें नंबर पर वाराणसी का नाम
- देश में रूफटॉप सोलर स्थापना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बनाया नया कीर्तिमान
- प्रदेश में 5.17 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर स्थापना के क्षेत्र में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के दो जिलों का शामिल होना तथा शीर्ष 50 जिलों में प्रदेश के पांच जिलों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे रूफटॉप सोलर बाजारों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रूफटॉप सोलर स्थापना के मामले में लखनऊ देश में पहले स्थान पर जबकि वाराणसी दसवें स्थान पर पहुंच गया है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5.17 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश पिछले एक वर्ष से देश में सर्वाधिक क्यूमूलेटिव रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन्स के साथ लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। प्रदेश में सोलर स्थापना की गति में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2025 तक जहां प्रतिदिन लगभग 500 संयंत्र स्थापित हो रहे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 2000 संयंत्र प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इस तीव्र वृद्धि के चलते प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये का व्यापारिक टर्नओवर उत्पन्न हो रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा मजबूत सोलर इकोसिस्टम अब केवल योजना आधारित क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य को देश के प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर रहा है। यूपीनेडा के निदेशक रविन्दर सिंह के अनुसार, राज्य नोडल एजेंसी के रूप में यूपीनेडा प्रभावी समन्वय और क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है। डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा तेज नेट मीटरिंग, मीटर



स्थापना और बिलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैंकिंग संस्थानों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स द्वारा सोलर फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर सहयोग और जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है।

उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां, ईपीसी कंपनियां और लॉजिस्टिक नेटवर्क भी तेजी से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा यूपीनेडा द्वारा संचालित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में प्रशिक्षित और कुशलता मानव संसाधन उपलब्ध हो रहा है, जो इस क्षेत्र की बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

उत्तर प्रदेश आज सोलर मैन्युफैक्चरर, ईपीसी कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, लॉजिस्टिक्स कंपनीज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स के लिए बड़े निवेश और व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। प्रदेश सरकार ने देशभर के रिन्यूएबल एनर्जी स्टेकहोल्डर्स से उत्तर प्रदेश की इस सोलर विकास यात्रा से जुड़कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास के मिशन में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

उत्तर प्रदेश में अब बच्चे होंगें संस्कारवान

अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ मिलेगी भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की सीख



योगी सरकार अब शिक्षा को भारतीय संस्कृति, संवाद कौशल और सामाजिक समावेश से जोड़ते हुए नई पीढ़ी को भारतीय भाषाई विरासत से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में 13 से 19 मई तक 'भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर-2026 आयोजित किए जाएंगे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख दी जाएगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति-2020 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए बहुभाषावाद और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। शिविर के दौरान बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं से परिचित होंगे। संवाद कौशल विकसित करेंगे और पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) की बुनियादी जानकारी भी प्राप्त करेंगे।

योगी सरकार शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर बच्चों को भारतीय संस्कृति, विविधता और सामाजिक संवेदनशीलता से जोड़ने का माध्यम भी बना रही है। यह शिविर भाषा सीखने के कार्यक्रम के साथ-साथ नई पीढ़ी को भारतीयता, सांस्कृतिक समरसता और राष्ट्रीय एकता से जोड़ने वाले अभियान के रूप में भी स्थापित हो रहा है।

योगी सरकार अब प्रदेश में शिक्षा को भारतीयता, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामाजिक समावेश से जोड़कर नई दिशा देने की ओर अग्रसर हो चुकी है। भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर-2026' आने वाले समय में बच्चों में संवाद क्षमता, भाषाई समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने वाला बड़ा अभियान बन सकता है।

बहुभाषावाद और भारतीय संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

शिविर का उद्देश्य बच्चों में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और बहुभाषावाद की समझ विकसित करना है।

इसके माध्यम से छात्र-छात्राओं को अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में भी बुनियादी संवाद कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय एकता की सबसे मजबूत कड़ी है। इसी सोच के अंतर्गत योगी सरकार द्वारा स्कूलों में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा को मजबूत करेगी सांकेतिक भाषा की पहल

शिविर में इंडियन साइन लैंग्वेज को शामिल किया जाना योगी सरकार की समावेशी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट-2016 के अनुरूप बच्चों को सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि समाज में संवेदनशीलता और समावेश की भावना को बढ़ावा मिल सके। एससीईआरटी द्वारा पीएम ई-विद्या चैनल के माध्यम से इंडियन साइन लैंग्वेज से जुड़ी शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों इसका प्रभावी उपयोग कर सकें।



भारत के तीर्थस्थल पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त : आक्रांताओं के खानदान का अता-पता नहीं : योगी

गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को श्रीशिव गोरखनाथ आश्रम में नवनाथों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व आठमान भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन की ताकत का अहसास कराने बागपत आया हूं। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी किसी पर जबरन आधिपत्य स्थापित नहीं किया। किसी को गुलाम नहीं बनाया। जब हम किसी पर जबरन शासन या भूमि पर कब्जा नहीं करते तो हमारा देश इसे कैसे स्वीकार कर सकता था। भारत लगातार विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा, सम-विषम परिस्थितियों में लड़ता रहा। जिन आक्रांताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मठ-मंदिरों, तीर्थस्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया, वे तीर्थस्थल पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो-निशान नहीं बचा। वे सब मिट्टी में मिल गए। उनके खानदान तक का भी अता-पता नहीं है।

देश व धर्म को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए

सीएम योगी ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करेंगे तो उससे नष्ट हुआ धर्म हमें भी नष्ट कर डालेगा। हमें जाने-अनजाने देश व धर्म को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए। व्यक्तिगत क्षति की भरपाई हो सकती है, लेकिन धर्म की क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। उसका खामियाजा वर्तमान



और भावी पीढ़ी भी भुगतेगी।

शक्ति हमारे सामर्थ्य की प्रतीक, यह विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण

सीएम योगी ने कहा कि आज 1000 वर्ष की दासता से मुक्ति के लिए सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा का अमृत पर्व भी है। 1026 में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। 1951 में आज ही के दिन प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के करकमलों से पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आज सोमनाथ मंदिर में उपस्थित रहे। मुझे भी काशी विश्वनाथ महादेव के चरणों में इस आयोजन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन अटल जी ने ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण में तीन परमाणु विस्फोट किए थे। यह बताता है कि हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य की प्रतीक तो है ही, विश्व कल्याण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

महाभारत कालीन है बागपत का इतिहास

सीएम योगी ने कहा कि बागपत का इतिहास महाभारत कालीन है। भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए कौरवों से जो पांच गांव मांगे थे, उनमें एक बागपत भी था। चार वर्ष पहले आया था तो यह बहुत छोटा सा स्थान था, लेकिन अर्जुन नाथ जी व उनके सहयोगी ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने इसे तीर्थ बना दिया है। विरासत की रक्षा ऐसे ही होती है। बागपत की इसी धरा ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जन्म दिया था। यहां के डॉ. सत्यपाल सिंह ने मुंबई पुलिस के मुखिया के रूप में कानून का शासन स्थापित किया। चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर बागपत समेत प्रदेश व देश के विकास के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित करने में सहायक हो रहा है।

आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। हम अतीत से जुड़कर ही उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान विस्मृत नहीं कर सकते। हम अयोध्या के लिए निरंतर लड़ते रहे और डबल इंजन सरकार आई तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। पूर्वजों ने हमें राम-राम का संबोधन दिया, क्योंकि जब भी अभिवादन करेंगे तो प्रभु का स्मरण करेंगे। राम मंदिर का निर्माण उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में रामजन्मभूमि, महाकाल में महालोक, केदारपुरी, विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार कार्य हुआ। प्रयास यही रहे कि हमारे घर ही नहीं, बल्कि तीर्थस्थल, देवी-देवताओं के स्थल भी सुरक्षित हों।

धर्म की अलख जगाई महायोगी गुरु गोरखनाथ ने

सीएम ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के योगी रूप हैं। योगी रूप में उन्होंने धर्म की अलख जगाने के लिए जनजागरण के विशाल कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। उनके सिद्धों, योगियों ने गुलामी कालखंड में भी जन-जागरण के अभियान को निरंतरता प्रदान की। वे योगी गांव-गांव जाकर सारंगीवादन व भजन के माध्यम से समाज को एकजुट कर विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए तैयार करते थे, यही उनकी राष्ट्रभक्ति थी। उनके भजनों में संदेश भी होता था कि आक्रांता आ रहा है, तैयार हो जाओ। इससे पहले कि वह आपके गांव व घर तक पहुंचे, उसका काम तमाम कर डालो। योगी सिर्फ गुफाओं, धूनी, मंदिरों तक सीमित नहीं रहे। धर्म व संस्कृति पर हमला होगा तो योगी बैठेगा नहीं, बल्कि मुकाबला कर मुंहतोड़ जवाब देगा। जो संकट के समय निडरता से खड़ा हो, वही संत है। संकट में पलायन करने वाला संत नहीं हो सकता।

भर्ती में न सिफारिश, न भ्रष्टाचार, सिर्फ योग्यता का सम्मान : योगी

मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर लोकभवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मिशन रोजगार" के अंतर्गत प्रदेश सरकार लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। पूरी प्रक्रिया में किसी को कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। परीक्षा के बाद भी किसी स्तर पर सिफारिश या अनैतिक साधनों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी साफ नीयत और स्पष्ट नीति का परिणाम है कि आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियां पैसों, जाति, मत, मजहब और क्षेत्र देखकर होती थीं, जिससे योग्य नौजवानों का शोषण होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योग्यता ही चयन का आधार बनी है। किसी योग्य अभ्यर्थी की जगह घूसखोर व्यक्ति व्यवस्था में आ जाता, तो वह अगले 30-35 वर्षों तक पूरे सिस्टम को घुन की तरह खोखला करता। इसलिए सरकार ने पहले दिन से ही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लीकेज की संभावनाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण आज यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।

15 दिनों के अंदर चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने नियुक्ति पत्र वितरण के नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपी के नौजवानों को निष्पक्ष, पारदर्शी व सहज प्रक्रिया से सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी। हमने अलग-अलग आयोगों व बोर्डों को जवाबदेही सौंपी और तकनीक का उपयोग कर हर योग्य नौजवान के साथ न्याय सुनिश्चित किया। इसी का परिणाम है कि हमने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर यह हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है।

यूपी को बना दिया गया था भ्रष्ट-गुंडा-अराजक प्रदेश



मुख्यमंत्री ने कहा कि याद कीजिए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश। देश-दुनिया में लोग यूपी का नाम सुनते ही शक की निगाह से देखते थे, दस कदम पीछे हट जाते थे। उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट, गुंडा और अराजक प्रदेश बनाकर हर यूपीवासी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अब आप कहीं भी जाएं, यूपी का नाम सुनते ही सामने वाले का चेहरा चमक उठता है, वह स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन का बदलाव और परिणाम भी उसी के अनुरूप हैं।

प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक बजट व अर्थव्यवस्था को तीन गुना किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक बजट व समग्र अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। यह सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला, किसानों को सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला और समाज के हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने वाला प्रदेश बन गया है।

96 लाख एमएसएमई इकाइयों में 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले एमएसएमई क्षेत्र लगभग बंद पड़ा था, कोई प्रोत्साहन नहीं था, चारों तरफ अव्यवस्था और हताशा थी। आज देश में सबसे अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्तर प्रदेश में हैं। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष यूपी में 4000 से अधिक बड़े उद्योग आए और पिछले 9 वर्षों में बड़े उद्योगों की संख्या 14,000 से बढ़कर 32,000 से अधिक हो गई है। जिस यूपी को पहले देश के बॉटम-3 राज्यों में गिना जाता था, आज टॉप-3 राज्यों में शामिल है।

आयुष के माध्यम से लाए जा सकते हैं चमत्कार



मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष हेल्थ टूरिज्म को आकर्षित करने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है। इसके माध्यम से चमत्कार लाए जा सकते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को गांव-गांव में और बेहतर बनाना है। उपचार की पारंपरिक विधाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन के लिए किसानों से संवाद स्थापित करना है। आज 202 प्राध्यापक, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब आयुष विभाग को और गति देंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्योग की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपावर

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग बड़ा और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अनुकूल वातावरण व नीतियों से यूपी में लगातार बड़े निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, इन उद्योगों को मांग के अनुरूप स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध कराना व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा इसके अनुदेशकों की जिम्मेदारी है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 150 से अधिक आईटीआई को आधुनिक बना दिया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हम कुशल प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन व अन्य टेक्नीशियन भी तैयार कर रहे हैं। आज नियुक्त होने वाले 272 ट्रेड अनुदेशक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हर दिव्यांगजन में प्रतिभा, बस सही प्लेटफॉर्म चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि "दिव्यांगजन सशक्तीकरण" नाम भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी कारण से दिव्यांगता का शिकार हो सकता है। हमारे मन में उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। हर दिव्यांगजन में प्रतिभा है, बस उसे सही प्लेटफॉर्म चाहिए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

पेंशन सुविधा दी, दो दिव्यांगजन विश्वविद्यालय स्थापित किए, हर कमिश्नरी मुख्यालय पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष केंद्र खोले गए और बंद पड़े डीआरसी (डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स) को पुनः चालू किया गया।

उत्तर प्रदेश में हर जनपद का पारंपरिक व्यंजन बनेगा पहचान

उत्तर प्रदेश के विविध स्वाद और समृद्ध खानपान परंपरा को नई पहचान देने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ओडीओपी की तर्ज पर 'एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी)' के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रमुख पारंपरिक व्यंजनों की व्यापक मैपिंग कर ली गई है, जिससे अब हर जिले की अपनी एक खास फूड आइडेंटिटी तय हो गई है। इस पहल में आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, वाराणसी की लस्सी, जौनपुर की इमरती, गोरखपुर के समोसे, मेरठ की रेवड़ी-गजक, लखनऊ का मलाई मक्खन, सहारनपुर का शहद और मुजफ्फरनगर का गुड़ जैसे प्रसिद्ध व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही अन्य जिलों के स्थानीय और पारंपरिक स्वाद जैसे कासगंज की सोन पापड़ी, अयोध्या की दही-जलेबी, बलिया का सत्तू, चित्रकूट का मावा और बागपत का घेवर भी इस सूची में शामिल किए गए हैं।

हर क्षेत्र का अलग स्वाद, एक ही पहचान

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ओडीओसी को लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। योजना के तहत ब्रज क्षेत्र की मिठास, अवध की समृद्ध कचौड़ी-समोसा संस्कृति, पूर्वांचल का देसी स्वाद और बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजन, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर 'टेस्ट ऑफ यूपी' की अवधारणा को मजबूत किया जा रहा है। इससे प्रदेश के खानपान की विविधता को एकीकृत पहचान मिलेगी। इस पहल का सीधा फायदा स्थानीय कारीगरों, हलवाई, छोटे दुकानदारों और फूड उद्यमियों को मिलेगा। पारंपरिक व्यंजनों की मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छोटे कारोबार को मजबूती मिलेगी।

पर्यटन में भी आएगा उछाल

योगी सरकार ओडीओसी को पर्यटन से जोड़कर फूड टूरिज्म को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है। अब पर्यटक किसी जिले में जाएंगे तो वहां के प्रसिद्ध व्यंजन का अनुभव लेना भी उनकी यात्रा का हिस्सा होगा। योगी सरकार की योजना है कि इन व्यंजनों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। इससे न सिर्फ यूपी के स्वाद को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक छवि भी और मजबूत होगी।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रमुख व्यंजन

1. आगराः पेठा /नमकीन (दालमोठ)/गजक/ पराठा
2. फिरोजाबादः आलू उत्पाद/ आलू टिक्की/कचौड़ी
3. मैनपुरीः सोहन पापड़ी/भुना हुआ आलू
4. मथुराः पेड़ा/छप्पन भोग/माखन मिश्री/ रबड़ी
5. अलीगढ़ः डेयरी उत्पाद/कचौड़ी/इमरती/इगलास के चमचम
6. हाथरसः रबड़ी
7. कासगंजः मूंग का दलमा/कलाकंद/सोन पपड़ी/सोरों की मोठ की चाट
8. एटाः चिकोरी/घेवर पूड़ी
9. अयोध्याः कचौरी/टिकिया/ पेड़ा/कुल्हड़ वाली दही जलेबी
10. सुलतानपुरः पेड़ा/समोसा/पूड़ी और कोहड़े की सब्जी/लाल पेड़ा
11. बाराबंकीः चंद्रकला मिठाई/लाल पेड़ा
12. अमेठीः समोसा/गुड़ की खीर/गुलगुला/बड़ी वाली पूड़ी
13. अंबेडकर नगरः बालूशाही/चाट/खजला/लाल गन्ने

की गोटी

14. आजमगढ़: तहरी (मूंग दाल की)/सफेद गाजर का हलवा/लौंगलता

15. बलिया: सत्तू आधारित उत्पाद/चाटी-चोखा

16. मऊ: लिट्टी-चोखा/गोंठा की भेली

17. बरेली: सेवइयां/बर्फी/ छोले-भटूरे/ चाट

18. बदायूं: खोआ आधारित मिठाई/पेड़ा/ पेड़े/लौज

19. पीलीभीत: जलेबी/खोआ मिठाई/लस्सी/लौज

20. शाहजहांपुर: लौंग बर्फी/गुड़/समोसे/खुरचन

21. बस्ती: ठेकुआ/पूरी-सब्जी/सिरका/गुड़

22. संत कबीर नगर: खोआ आधारित मिठाई/समोसा/पेड़ा

23. सिद्धार्थनगर: खोआ आधारित मिठाई (गम-कचौरी)/मखाना/कालानमक चावल/गमकटोरी

24. बांदा: सोहन हलवा/बालूशाही

25. चित्रकूट: मावा

26. हमीरपुर: बुंदेली व्यंजन (दाल भरे/डुबरी फरा/महुआ बर्फी/माड़े/सन्नाटा)

27. महोबा: दाल बाफला/तिलकुट/देसावरी पान/खजूर का गुड़

28. गोंडा: इंटियाथोक का दही बड़ा व कचौड़ी

29. बहराइच: चमचम

30. बलरामपुर: नारियल बर्फी/कलाकंद/ घमंजा/ चाट

31. श्रावस्ती: इमरती

32. गोरखपुर: लिट्टी-चोखा/लहसुन वाले छोले समोसे/ बर्फी

33. महराजगंज: लिट्टी-चोखा/खोआ आधारित मिठाई (गम-कचौरी)/गुड़/मीठा समोसा

34. देवरिया: मालपूआ/लिट्टी-चोखा/दही/गुड़ की जलेबी

35. कुशीनगर: केला चिप्स/पेड़ा/लाल खोरमा

36. झांसी: दाल बाफला/बालूशाही

37. जालौन: रसगुल्ले/गुझिया

38. ललितपुर: दूध हलवा/बाजरे की रोटी

39. कानपुर: समोसा/लड्डू/मलाई मक्खन (मलइयो)

40. कानपुर देहात: खाद्य तेल/लस्सी

41. औरैया: शुद्ध देसी घी/दूध बर्फी मिठाई/बालूशाही/ गुड़

42. इटावा: सरसों आधारित उत्पाद (सरसों की चटनी/सलाद) मट्ठा के आलू/खीर मोहन

43. फर्रुखाबाद: दालमोठ/भुने आलू

44. कन्नौज: गट्टा मिठाई/खोआ का पेड़ा

45. लखनऊ: रेवड़ी/आम उत्पाद/चाट/मलाई मक्खन

46. हरदोई: आलू पूरी/लड्डू/लाओझड़

47. लखीमपुर खीरी: केला/गुड़/खोआ पेड़ा/खीर मोहन/रसगुल्ले

48. रायबरेली: मसाले

49. सीतापुर: मक्खन मलाई/समोसा/मिर्ची पकौड़ा/पेड़ा

50. उन्नाव: काला जामुन/समोसा/कचौड़ी/त्रिलोक परी

51. मेरठ: रेवड़ी/गजक/नानखटाई

52. गाजियाबाद: सोया चाप/मिर्ची का अचार

53. गौतम बुद्ध नगर: केक/बेकरी उत्पाद

54. हापुड़: पापड़

55. बुलंदशहर: कचौरी/खुरचन/पेड़ा

56. बागपत: बालूशाही/घेवर

57. मिर्जापुर: लाल पेड़ा/बालूशाही/रसगुल्ला/पेड़ा

58. भदोही (संत रविदास नगर): दाल पीठा/ठेकुआ/खोआ पेड़ा/गुझिया/रेवड़ी

59. सोनभद्र: गुलाब जामुन

60. मुरादाबाद: दाल

61. रामपुर: हल्दी हलवा (हलवा)

62. अमरोहा: आम पन्ना/आम चटनी/सेव/लड्डू

63. संभल: सेवइया/गजक/सोनपापड़ी

64. बिजनौर: गजक/सिंघाड़ा कचौरी/सोनपापड़ी और बतीसा

65. प्रयागराज: सब्जी-कचौरी/समोसा/रसगुल्ला

66. फतेहपुर: बेड़मी पूरी-सब्जी/पेड़ा/सूतफेनी

67. कौशांबी: गुड़ से बनी मिठाई/चाट/बर्फी/मूंगौरा

68. प्रतापगढ़: आंवला आधारित उत्पाद/गुलाब जामुन

69. वाराणसी: तिरंगा बर्फी/ठंडाई-लस्सी/कचौरी/बनारसी पान/लौंग लत्ता/मलइयो

70. जौनपुर: इमरती/मिठाई एटमबम/जौनपुरी मूली

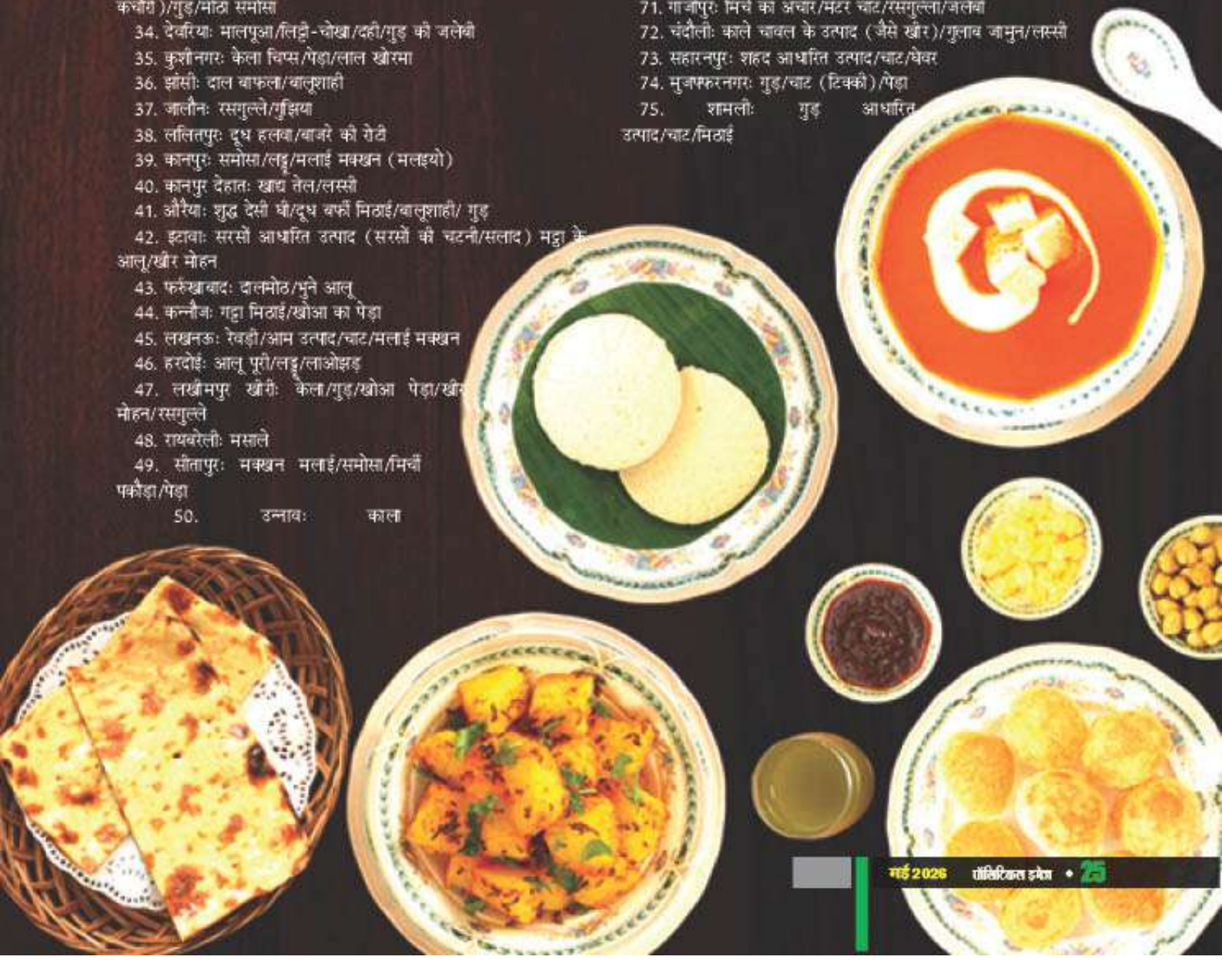
71. गाजीपुर: मिर्च का अचार/मटर चाट/रसगुल्ला/जलेबी

72. चंदौली: काले चावल के उत्पाद (जैसे खीर)/गुलाब जामुन/लस्सी

73. सहारनपुर: शहद आधारित उत्पाद/चाट/घेवर

74. मुजफ्फरनगर: गुड़/चाट (टिक्की)/पेड़ा

75. शामली: गुड़ आधारित उत्पाद/चाट/मिठाई





युवा शक्ति को मिलेगा हुनर का साथ, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा स्किल हब

योगी सरकार की नई पहल से 13 विभागों के युवाओं को मिलेगा उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार सक्षम बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) ने राज्य को देश का अग्रणी "स्किल हब" बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। प्रदेश के 13 प्रमुख विभागों को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रस्ताव भेजते हुए आगामी तीन महीनों में बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगारपरक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमशीलता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

हर वर्ग तक पहुंचेगा कौशल विकास अभियान

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों, ग्रामीण युवाओं,



महिला स्वयं सहायता समूहों, अल्पसंख्यक समुदाय, निर्माण श्रमिक परिवारों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तथा कारागारों से जुड़े युवाओं को उनकी रुचि और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योगी सरकार की यह पहल सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में देखी जा रही है। विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के युवाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के हर जिले में तैयार होगी हुनरमंद युवा शक्ति

राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कौशल विकास को युवाओं की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग तक कौशल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागीय समन्वय के साथ तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मिशन निदेशक पुलकित



खरे द्वारा संबंधित विभागों को पत्र जारी कर प्रशिक्षण लक्ष्य एवं कार्ययोजना साझा करने का अनुरोध किया गया है। जून माह के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन किए जाने की संभावना है। साथ ही सभी विभागों से नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन तेजी से किया जा सके।

जेलों में भी शुरू होगा कौशल प्रशिक्षण अभियान

योजना के अंतर्गत कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के माध्यम से जेलों में निरुद्ध युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य उन्हें प्रशिक्षण देकर पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके अलावा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा प्रशिक्षण

पुलकित खरे ने बताया कि यूपीएसडीएम को राष्ट्रीय स्तर पर एनसीवीईटी द्वारा 'अवार्डिंग बॉडी' की मान्यता प्राप्त है, जिससे प्रशिक्षण और प्रमाणन की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। वर्तमान में मिशन से राजकीय संस्थानों के साथ प्रतिष्ठित निजी और औद्योगिक इकाइयां भी प्रशिक्षण पार्टनर के रूप में जुड़ी हुई हैं। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के 'कॉस्ट कॉमन नॉर्म्स' (सीसीएन) के अनुरूप संचालित किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित होंगी।



आठ लाख से अधिक युवाओं को मिला प्रशिक्षण

मिशन निदेशक ने बताया कि यूपीएसडीएम का उद्देश्य 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अल्पकालीन, रोजगारपरक एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। पिछले 9 वर्षों में मिशन द्वारा 8,09,494 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 3,04,810 युवाओं को रोजगार एवं सेवायोजन के अवसरों से जोड़ा गया है। यह उपलब्धि योगी सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें युवा शक्ति को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार माना गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाना है।

13 विभागों के साथ मिलकर चलेगा अभियान

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), संयुक्त आयुक्त उद्योग कार्यालय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय को प्रशिक्षण प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि विभागीय समन्वय से संचालित यह अभियान लाखों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

सड़कों पर उतरा असंतोष

वेतन विवाद से उभरा नोएडा
सरकार की अंतरिम राहत से थमी आग

उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थिति अचानक बदल गई। कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन सड़क तक पहुंचा। पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के जरिए उन्हें शांत करा लिया। हालांकि, निजी कंपनियों के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। सड़कों पर उतरे कर्मचारियों ने कानून और नियमों को धत्ता बताते हुए सड़क पर डेरा जमा लिया। नोएडा में कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन को अचानक उग्र कर दिया। स्थिति यह हो गई कि प्रशासन को स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल को उतारना पड़ा। नोएडा डीएम मेधा रूपम को भी प्रदर्शनकारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए। कर्मचारियों के हितों को लेकर भी कंपनियों और उद्योगों को श्रम कानूनों का सही ढंग से पालन करने का निर्देश दिया गया।



क्यों भड़का विवाद?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनियों के कर्मचारियों का विवाद न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर भड़का हुआ है। विवाद कपड़ों के निर्यात इकाइयों के कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन से शुरू हुआ। दरअसल, प्रदेश की कंपनियों में न्यूनतम वेतन काफी कम होने की बात सामने आई है। कई कंपनियों में कर्मचारियों को 12 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये किए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी बढ़ती महंगाई के बीच इस वेतनमान में घर चला पाने की स्थिति में नहीं हैं। यही मुद्दा वे लगातार कंपनी प्रबंधन के समक्ष उठा रहे थे।

कंपनी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को ठोस आश्वासन नहीं मिला। मामला गरमाया तो पहले सरकार या प्रशासन की तरफ से भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शन के दौरान गोली चलने और महिला कर्मचारी के घायल होने के बाद इस विवाद पर हर किसी की नजर गई। कर्मचारियों का कहना है कि महानगर में सर्वाइव करना इस वेतन में संभव नहीं हो पा रहा है। एलजीपी सिलेंडर महंगे होने से और दिक्कत हुई।

पुलिस को देखकर भड़का गुस्सा



प्रदर्शन शुरुआती दौर में कंपनी के गेट तक सीमित था। कर्मचारी अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे। इसी बीच पुलिस को औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन की सूचना दी गई। पुलिस मामले की सूचना के बाद पहुंची तो उसने अधिकारियों से बातचीत का भरोसा दिलाया। अधिकारियों तक मामले को नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया। प्रदर्शन में नारेबाजी तेज हुई तो उन्हें संभालने और अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए। कंपनियों के बाहर पुलिस को देखकर कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई। बाद में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर कर्मचारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। आगजनी का भी मामला सामने आया है।

कर्मचारियों की मांगें?

समान वेतन दिया जाए: कर्मचारियों की मांग समान वेतन की है। उनका कहना है पड़ोस के हरियाणा में समान ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन में 35 फीसदी की वृद्धि हुई है। यहां पर 200 से 300 रुपये बढ़ाए गए। अब कर्मचारी एकरूपता की मांग कर रहे हैं। इस पर कंपनियां सहमत होती नहीं दिखी हैं।

ओवरटाइम-बोनस दिया जाए: फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों में ओवरटाइम को लेकर नए श्रम कानूनों के तहत दोगुना पेमेंट का प्रावधान है। बोनस को बैंक खातों में दिया जाना है। इसमें कई कंपनियों में आनाकानी करती दिखी। हालांकि, डीएम मेधा रूपम ने कर्मचारियों को ओवरटाइम और बोनस के नियमों का पालन कराने का आश्वासन दिया है।

सैलरी का लेकर मांग: कर्मचारियों ने सैलरी स्लिप और समय पर वेतन जारी किए जाने की मांग की है। महीने की 10 तारीख तक हर हाल में वेतन मिले, इसकी मांग की गई है। सैलरी स्लिप न मिलने से मनमाफिक कटौती की बात कही जा रही है।

मिले वीकली ऑफ: कर्मचारियों का आरोप है कि कई कंपनियां वीकली ऑफ नहीं दे रही हैं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी हर हाल में मिले। अगर ऑफ दिन काम कराया जाए तो उसका दोगुना भुगतान हो। कर्मचारियों का कहना है कि इस नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। नोएडा डीएम ने इस पर भी सहमति दी है।

वर्कप्लेस का बेहतर वातावरण: कर्मचारियों की मांग वर्कप्लेस के माहौल में सुधार की है। पुरुष और महिला कर्मी सुरक्षित और कामकाजी माहौल में काम करें, इसके लिए श्रम कानून के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाए। डीएम ने इस पर भी अपनी रजामंदी दी है। औद्योगिक इकाइयों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है।

श्रमिकों के वेतन में 21% तक वृद्धि

नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि का ऐलान किया है। हालिया घटनाक्रमों के बाद की गई विस्तृत समीक्षा के आधार पर सरकार ने संतुलित निर्णय लेते हुए अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणियों में करीब 3000 तक वेतन बढ़ाया है, जिससे गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 21% तक वृद्धि हुई है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सरकार ने 20,000 न्यूनतम वेतन की खबरों को भ्रामक बताया है, वहीं श्रमिकों की मांगों और उद्योगों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे वेज बोर्ड के माध्यम से स्थायी समाधान की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश दीपक कुमार ने हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यूनतम वेतन में तात्कालिक रूप से अंतरिम वृद्धि का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी कुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए की गई है, वहीं गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में यह वृद्धि सबसे अधिक 21 प्रतिशत तक की गई है और यह नई अंतरिम वेतन दरें 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।

अंतरिम वेतन वृद्धि के अनुसार अकुशल श्रमिकों का वेतन 11313 से बढ़ाकर 13690 कर दिया गया है, अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12445 से बढ़ाकर 15059 किया गया है, जबकि कुशल श्रमिकों का वेतन 13940 से बढ़ाकर 16868 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए अकुशल श्रमिकों का वेतन 11313 से बढ़ाकर 13006, अर्ध कुशल श्रमिकों का वेतन 12445 से बढ़ाकर 14306 तथा कुशल श्रमिकों का वेतन 13940 से बढ़ाकर 16025 कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य जनपदों के लिए अकुशल श्रमिकों का वेतन 11313 से बढ़ाकर 12356, अर्ध कुशल श्रमिकों का वेतन 12445 से बढ़ाकर 13591 तथा कुशल श्रमिकों का वेतन 13940 से बढ़ाकर 15224 कर दिया गया है।

कन्ट्रोल रूम स्थापित

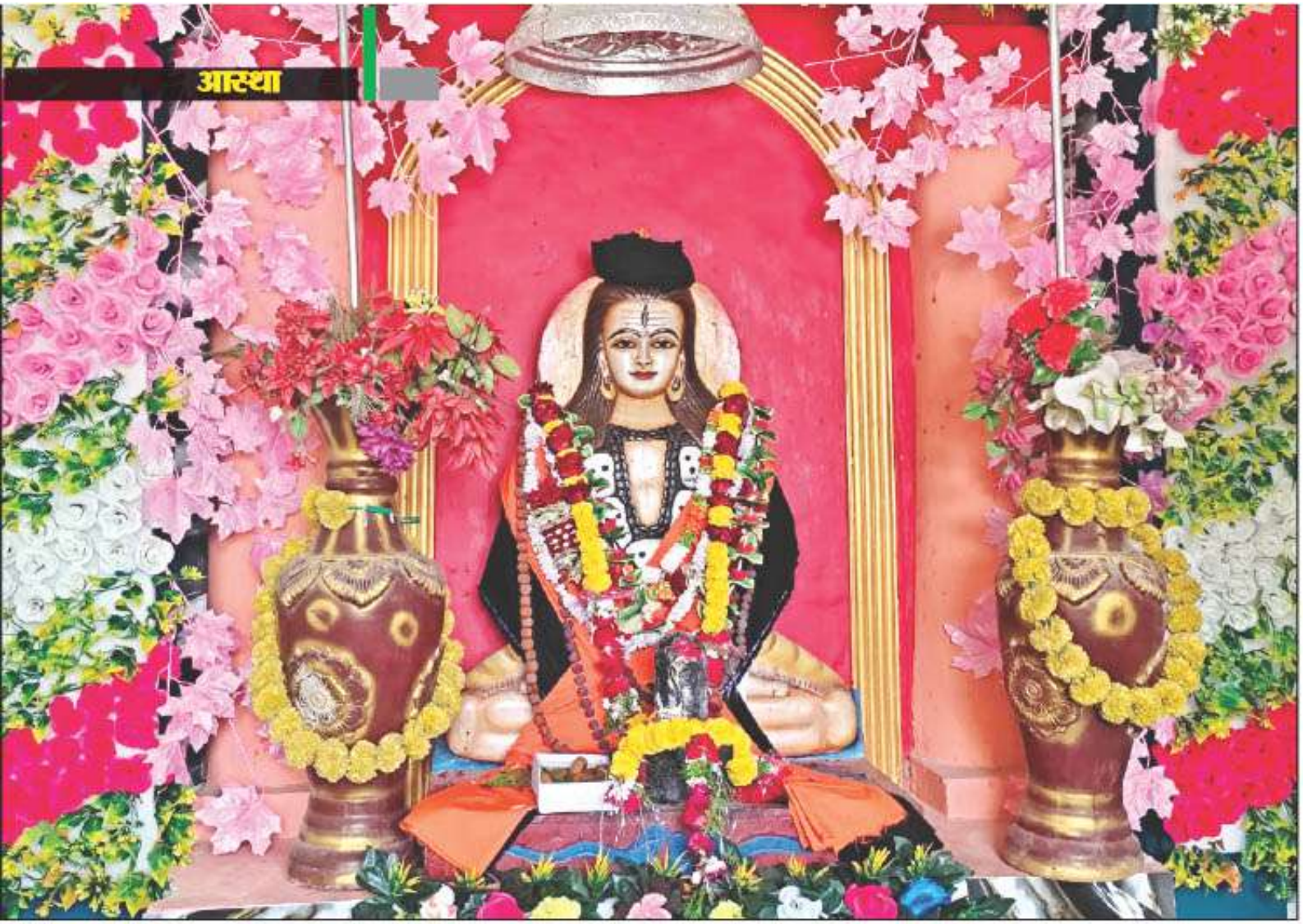
समिति द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि जनपद स्तर पर श्रमिकों के वेलफेयर एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके नम्बर 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862, 120-2978702 हैं, इस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से श्रमिक अपनी किसी भी प्रकार की समस्या, शिकायत अथवा सूचना दर्ज करा सकते हैं।

पुलिस कमिश्नर का खुलासा

नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच कुछ अवांछनीय तत्व पाकिस्तानी एजेंडा पूरा कर रहे थे। श्रमिकों के विरोध को हाईजैक करने के लिए दो सोशल मीडिया अकाउंट लगातार पाकिस्तान से सक्रिय थे, जिससे 13 अप्रैल को भड़का बवाल हिंसा में बदल गया। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को इसके साक्ष्य भी मिले हैं। लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों से नोएडा में शांति है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बहाल करने फ्लैग-मार्च निकाला। नोएडा क्षेत्र की सभी इंडस्ट्रियल यूनिटों में एक से तीन शिफ्टों में श्रमिकों से शांतिपूर्वक काम किया गया।

पाकिस्तान ने रची साजिश

लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 13 अप्रैल को भीड़ ने बवाल किया था और पुलिस ने उसको नियंत्रित किया। हालांकि दोपहर में बवाल शांत होने के बाद दो सोशल मीडिया हैंडल के जरिए झूठा नरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस की फायरिंग में मजदूरों की मौत का भ्रम भी फैलाया गया। मामले को ट्वीट के जरिए वायरल कराया गया। इसके बाद वापस लौट रहे श्रमिक भड़क उठे थे। इन दो एक्स हैंडल के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में मुकदमे लिखे गए। विवेचना के दौरान एक्स से मिली डिटेल में सामने आया कि ये दोनों हैंडल लगातार पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे।



सत्यनाथी-पंथ के संस्थापक सत्यनाथ के मठ की ऐतिहासिकता



श्यामचन्द्र श्रीवास्तव

उद्गम से संगम तक गोमती तट आज भी आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बिंदु बना है। अनेक मोड़, घुमाओं, गोखुर एवं छाड़ झील का निर्माण करते हुए गोमती तीरे साधना, साहित्य, राजनैतिक, आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र बिन्दु जनपद सुल्तानपुर में स्थित बिजेथुआ महावीरन हनुमान लला की छत्रछाया में जनपद की पूर्वी सीमा पर 26 अंश 10 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 82 अंश 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 26 अंश 17 मिनट उत्तरी अक्षांश और 82 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य समुद्र तल से 95 मीटर की ऊंचाई पर कादीपुर तहसील का मुख्यालय स्थित है।

ब्रह्मा के अवतार सत्यनाथ के समर्पण का इतिहास उस कथा से जुड़ा है जिसमें विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह बहस हुई थी कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में शिव आदिनाथ प्रकट हुए। विष्णु उस स्तंभ का उद्गम स्थल खोजने पाताल लोक गए और ब्रह्मा स्वर्ग लोक गए, लेकिन उनमें से कोई भी न तो आदि और न ही अंत पा सका। इसके बाद गोरक्षनाथजी बालक रूप में अग्नि से प्रकट हुए और उनकी आज्ञा से प्रकाश प्रवाहित हुआ। उन्होंने ब्रह्मा से कहा अगले अवतार में तुम मेरे समान होगे। तुम जल में जन्म लोगे, वेदों, पुराणों, शास्त्रों, नक्षत्रों, ग्रहों, राशियो, काल, संध्या, तर्पण, तंत्र,

मंत्र, गायत्री का ज्ञान प्राप्त करेगे और पृथ्वी पर सत्यनाथ के रूप में अवतरित होगे जहाँ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे।र

विद्वान यह मानते हैं कि भारशिव सम्राट अल्वे ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में कादीपुर तहसील अन्तर्गत अल्देमऊ नूरपुर गांव स्थित गोमती नदी के तट पर बाबा सत्यनाथ से प्रभावित होकर एक किला बनवाया था, किले के बगल टीले पर ठीक उसके नीचे एक गहरी गुफा आज भी है, जिसका निकास द्वार ऊपर से होता हुआ नीचे पश्चिम तरफ गोमती की धार के करीब खुलता है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बाबा सत्य नाथ के मठ की एक अमर कथा कहता है जो प्रबुद्ध मस्तिष्क के चिंतन का अपने में एक विषय बन गया है। ईश्वर स्वयं जब चाहते हैं तो अपने अनुसार किसी न किसी महापुरुष से अपने अनुकूल कार्य करवा ही लेते हैं। वस्तुतः यह संस्थान के छिपे अनेक रहस्यों के उद्घाटन हेतु ईश्वर ने काशी के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा को यहां आश्रम एवं मठ के विकास लिए प्रेरित किया, और आज कपाली बाबा के अथक प्रयास और साधना के परिणाम स्वरूप यह स्थान जनमानस के आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितम्बर 2025 में इसे पर्यटन स्थल घाषित किया है।

ब्रम्हा जी के अवतार माने जाने वाले योगीराज अघोराचार्य बाबा सत्यनाथ का यह पावन स्थल आदि गंगा गोमती और लुप्त प्राय प्राचीन चन्द्रभागा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। चूँकि आदि गंगा गोमती जहां से दक्षिण वाहिनी होकर पुनः दक्षिण वाहिनी हुई हैं (यथा दक्षिण से पूर्व और पूर्व से पुनः दक्षिण) विष्णुपुराण व स्कन्द पुराण के अनुसार मां गोमती के इस दक्षिण मार्गी प्रवाह को धूत पापा कहा गया है। यह दक्षिण मार्गी नदी का पूरा क्षेत्र धोपाप के नाम से विख्यात है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम ने लंकाधिपति रावण के बध से उत्पन्न पाप के समन के लिए यहीं आकर स्नान किया था। इसी धोपाप के दक्षिणीय या अन्तिम छोर पर स्थित है। यह पुण्यतम तपोभूमि अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ मठ। श्रीराम के सुपरिचित क्षेत्र होने के कारण ही उनके अश्वमेध यज्ञ का आमंत्रण देने हेतु श्री हनुमान जी यहां पधारे और मठ के समीप यह स्थल श्री हनुमान टेकरी के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीनतम मठ का जीवर्णोधार मथुरा के शकछत्रक या नाग वंशी छत्रक रूद्र सिंह द्वितीय ने तथा महाराजा विक्रमादित्य और सम्राट हर्ष वर्धन के द्वारा समय-समय पर कराया गया। जब जौनपुर में शर्की सल्तनत ने इब्राहिम शाह शर्की का शासन था जो देवालयों के विध्वंस के लिए कुख्यात था और काशी समेत कई धार्मिक नगर उसकी धर्मान्धता के शिकार हुये उसी के द्वारा 1440 के आस-पास राजा अल्दे के हर्ष वर्धन कालीन किले पर आक्रमण हुआ तो किले के निकट स्थित इस प्राचीनतम मठ का भी विध्वंस कर दिया गया। काल प्रवाह से यह मठ जन सामान्य की दृष्टि से विस्मृत हो सघन वन्य क्षेत्र से आक्षादित हो गया परन्तु जन भावनायेंइ स मठ से जुडी रहीं और लोगो के हृदय में बाबा सत्यनाथ और उनसे जुडी कथायें, चमत्कार सदैव गुजरते रहें। आज भी चौहान वंश के राजकुमार छत्रि तथा स्वयं को ईशानवर्मा से सम्बद्ध करने वाले कुर्मी वंशीय क्षत्रि बाबा सत्यनाथ को अपना कुल गुरु या पूर्वज मानते है। प्राचीन भारत के राजाओं में प्रसिद्ध भौखरि नरेश राजा आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराजा विक्रमादित्य, हिन्दू धर्म के पुनरोद्धारक पुष्यमित्र शुंग का इतिहास इस मठ से जुड़ा हुआ है। विधर्मियों ने कई बार इस पर अनाधिकृत रूप से अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। परन्तु बाबा सत्यनाथ की कृपा व हिन्दू जनमानस की अगाध आस्था से वे अपने इस प्रयास में कभी सफल नहीं हो पाये। मठ का इतिहास त्रेतायुग से कलिकाल तक जन मानस की दन्त कथाओं एवंज न सुतियों में पूरी तरह सुरक्षित है।

वस्तुतः गोमती नदी एक मजबूत संस्कृति की सम्वाहिका है। भागवत पुराण के अनुसार गोमती पंचदेव नदियों में से एक है जो 25 अंश 30 मिनट 29 सेकंड उत्तरी अक्षांश एवं 83 अंश 10 मिनट 11 सेकंड पूर्वी देशांतर पर पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत नामक ताल से प्रारंभहोकर लगभग 960 किलोमीटर अजस्र प्रवाह पूर्ण कर 25 अंश 50 मिनट 8 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 अंश 16 मिनट 10 सेकंड पूर्व देशांतर पर गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप गंगा जी में समाहित हो जाती है। गोमती के 960 किलोमीटर के यात्रा में अनेक आडे, तिरछे, सीधे तथा घुमावदार मोड आते है। गोमती के तटों पर अनेकानेक मंदिर वेद मंत्रों से आज भी गुजारित हो रहे हैं। इन मंदिरों में शैव मठों का अधिक विस्तार है।

उद्गम से संगम तक गोमती तट आज भी आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बिंदु बना है। अनेक मोड़, घुमाओं, गोखुर एवं छाड़ झील का निर्माण करते हुए गोमती तीरे साधना, साहित्य, राजनैतिक, आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र बिन्दु जनपद सुल्तानपुर में स्थित बिजेथुआ महावीरन हनुमान लल्ला की छत्रछाया में जनपद की पूर्वी सीमा पर 26 अंश 10 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 82 अंश 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 26 अंश 17 मिनट उत्तरी अक्षांश और 82 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य समुद्र तल से 95 मीटर की ऊंचाई पर कादीपुर तहसील का मुख्यालय स्थित है। कादीपुर चौराहे से दक्षिण चांदा मार्ग पर लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण मार्ग के पूरब तरफ ग्राम सभा अल्देमऊ नूरपुर बसा है। अल्देमऊ भरे के शासनकाल में प्रतापी भर राजा अल्दे की राजधानी हुआ करता था। ग्राम सभा के दक्षिणी पूर्वी छोर पर गोमती का अद्भुत समकोणीय घुमाव है जो उद्गम से संगम तक एक ही जगह परलक्षित होता है। इस लम्बकोणी घुमाव बिंदु पर अपने में अनेक रहस्य आत्मसात करता हुआ सत्य नाथ मठ स्थापित है। यह मठ लगभग 5000 साल पुराना शिव साधना केंद्र है जो अपनी भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण अपनी अलग पहचान रखता है।

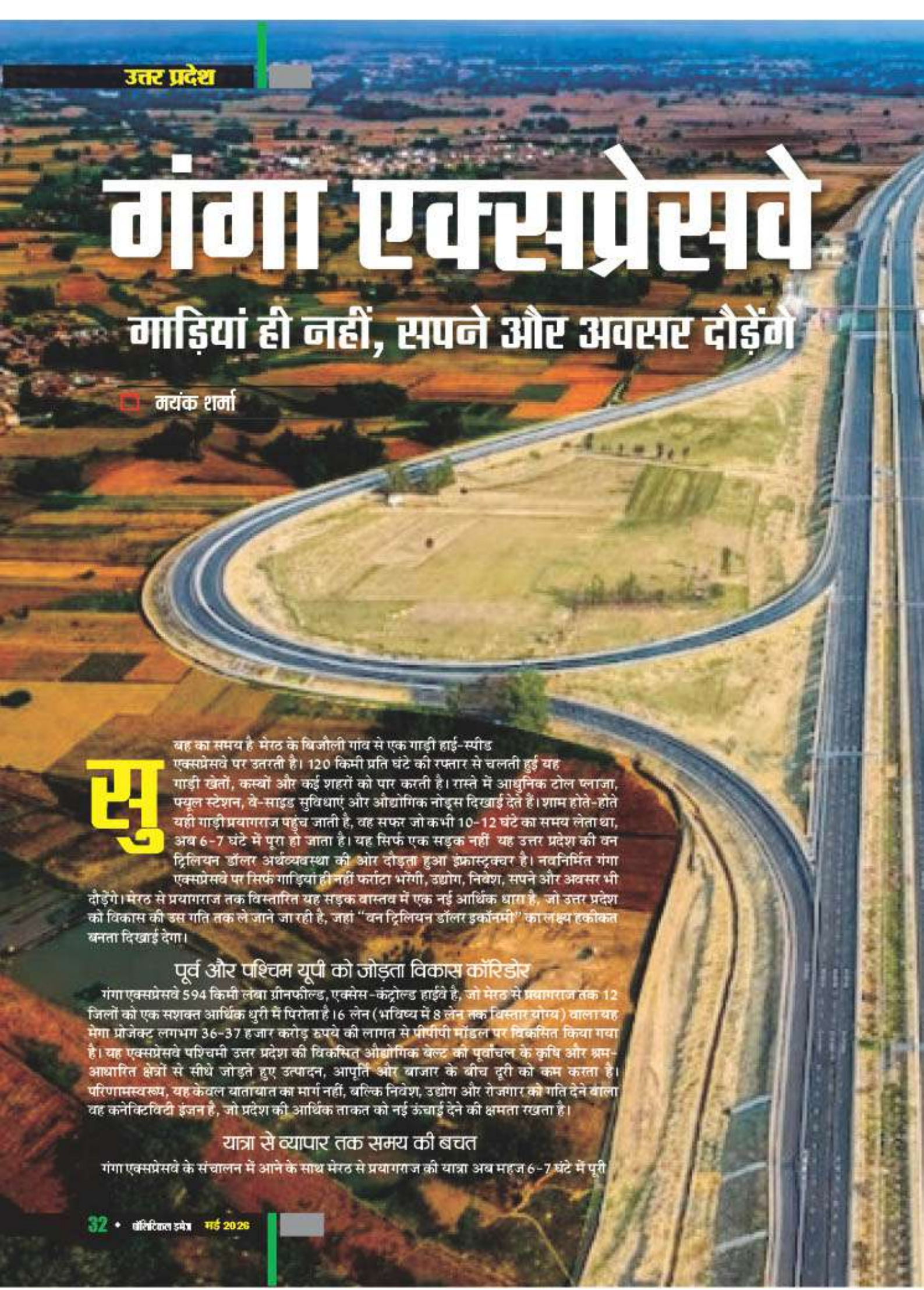
अघोर परम्परा में साधना की 5 धाराएं हादि, कादि, क्रोधादि, वागादि और प्रणवादि हैं, जिन्हें अघोर साधक अपने स्तर से साधनाएं करते हैं. ऐसा माना जाता है कि कादीपुर नामक स्थान भी बाबा सत्यनाथ ने ही बसाया था। बाबा सत्यनाथ कादिधारा के प्रवर्तक थे। वर्तमान में शिवलिंग और अर्घा के रूप में मौजूद कादिधारा यन्त्र इस बात का प्रमाण है कि बाबा सत्यनाथ द्वारा बसाये गए गांव अथवा नगर को कादीपुर कहा गया। इस मठ के प्रमाण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां मौजूद किला और किले की दीवारें आज भी दिखाई देती हैं, जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं. 90 अंश के कोण पर मुड़ी गोमती नदी के किनारे इस मठ के इर्द-गिर्द बड़े-बड़े टीले मौजूद है, जो शांत वातावरण तैयार कर साधना क्रम में ऊर्जा प्रदान करते हैं. पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण स्थल है. हरिश्चंद्र घाट, बनारस के श्मशान पीठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा वीरान पड़े इस शैव साधना स्थल के गौरव को पुनः वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा की कृपा एवं प्रयास से शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्यनाथ मठ को पर्यटन स्थल घोषित कर इसके विकास के लिए एक करोड रुपये का प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किया है।

पौराणिक ग्रंथों में अवधूत सम्प्रदाय के संतों की जो विशेषताएं बताई हैं प्रायः सभी पूज्य कपाली जी महाराज में परिलक्षित होती हैं। अवधूतोपनिषद् में अवधूत के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। अवधूत गीता प्रभृति ग्रन्थों में भी यह विषय चर्चित है। तदनुसार अवधूत के प्रत्येक वाक्य में वेद निवास करते है, पद-पद में तीर्थ बसते हैं. इसकी कृपा दृष्टि में कैवल्य विराजमान है। इसके एक हाथ में त्याग है और दूसरे में भोग। फिर भी यह त्याग और भोग दोनों से अलिप्त रहता है। वह वर्णाश्रम से परे है. समस्त गुरुओं का गुरु है। न उससे कोई बड़ा है और न बराबर। पक्षपात विनिर्मुक्त मुनीश्वर को ही अवधूत कहा जाता है। उसे ही नाथ पद प्राप्त हो सकता है। इस अवधूत का परम पुरुषार्थ मुक्ति है, जो द्वैत और अद्वैत के द्वंद्व से परे है। यह मत वेदान्त, सांख्य, मीमांसा, बौद्ध, जैन प्रभृति सभी दर्शनों से विलक्षण है। नाथ सम्प्रदाय को ही अवधूत मत या अवधूत सम्प्रदाय

गंगा एक्सप्रेसवे

गाड़ियां ही नहीं, सपने और अवसर दौड़ेंगे

मयंक शर्मा



सुबह का समय है. मेरठ के बिजौली गांव से एक गाड़ी हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर उतरती है। 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई यह गाड़ी खेतों, कस्बों और कई शहरों को पार करती है। रास्ते में आधुनिक टोल प्लाजा, फ्यूल स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और औद्योगिक नोड्स दिखाई देते हैं। शाम होते-होते यही गाड़ी प्रयागराज पहुंच जाती है, वह सफर जो कभी 10-12 घंटे का समय लेता था, अब 6-7 घंटे में पूरा हो जाता है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं यह उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर दौड़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं फर्राटा भरेंगी, उद्योग, निवेश, सपने और अवसर भी दौड़ेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक विस्तारित यह सड़क वास्तव में एक नई आर्थिक धारा है, जो उत्तर प्रदेश को विकास की उस गति तक ले जाने जा रही है, जहां "वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी" का लक्ष्य हकीकत बनता दिखाई देगा।

पूर्व और पश्चिम यूपी को जोड़ता विकास कॉरिडोर

गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी लंबा ग्रीनफील्ड, एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे है, जो मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को एक सशक्त आर्थिक धुरी में पिरोता है। 6 लेन (भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य) वाला यह मेगा प्रोजेक्ट लगभग 36-37 हजार करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकसित औद्योगिक बेल्ट को पूर्वांचल के कृषि और श्रम-आधारित क्षेत्रों से सीधे जोड़ते हुए उत्पादन, आपूर्ति और बाजार के बीच दूरी को कम करता है। परिणामस्वरूप, यह केवल यातायात का मार्ग नहीं, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार को गति देने वाला वह कनेक्टिविटी इंजन है, जो प्रदेश की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखता है।

यात्रा से व्यापार तक समय की बचत

गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन में आने के साथ मेरठ से प्रयागराज की यात्रा अब महज 6-7 घंटे में पूरी



हो सकेगी, जबकि पहले यही दूरी तय करने में 10-12 घंटे लगते थे। यह समय की बचत सीधे तौर पर लॉजिस्टिक्स लागत में कमी का आधार बनेगी। तेज और निर्बाध आवागमन से सप्लाई चेन अधिक प्रभावी होगी, जिससे कृषि उत्पादों को खेत से बाजार तक पहुंचने में कम समय लगेगा और उनकी गुणवत्ता व मूल्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। साथ ही, ई-कॉमर्स, वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को नई गति मिलेगी। दरअसल, समय की यह बचत ही आर्थिक दक्षता में बदलती है और यही दक्षता किसी भी राज्य की विकास गति को कई गुना बढ़ा देती है।

12 जिलों में 'इकोनॉमिक रेवोल्यूशन'

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 जिलों को जोड़ते हुए एक व्यापक आर्थिक परिवर्तन की नींव रखता है। इन जिलों की भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं के अनुरूप विकास की नई संभावनाएं उभर रही हैं। मेरठ-हापुड़ में मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स गुड्स, बुलंदशहर-अमरोहा में फूड प्रोसेसिंग और डेयरी, शाहजहांपुर-हरदोई में एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री, उन्नाव-रायबरेली में टेक्सटाइल और एमएसएमई, जबकि प्रयागराज लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो सकता है। इस तरह, यह एक्सप्रेसवे अलग-अलग आर्थिक क्षमताओं वाले इन जिलों को एकीकृत करते हुए उन्हें एक सिंगल, इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक नेटवर्क में बदल देता है, जहां उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण एक ही विकास धारा में प्रवाहित होते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम

गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर के रूप में तैयार किया गया है, जो परिवहन के साथ-साथ औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला रखता है। इसमें 2 मुख्य टोल प्लाजा और 19 रैंप टोल के साथ सुगम प्रवेश-निकास व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जबकि 9 आधुनिक जन-सुविधा परिसरों में फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन और रेस्ट एरिया जैसी सुविधाएं यात्रियों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा, 960 मीटर लंबा गंगा ब्रिज और 720 मीटर का रामगंगा ब्रिज जैसी इंजीनियरिंग संरचनाएं इसकी क्षमता को और मजबूत बनाती हैं। 120 मीटर का राइट ऑफ वे भविष्य में विस्तार और अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराता है। समग्र रूप से यह एक्सप्रेसवे एक ऐसी सुविचारित संरचना है, जिसे लॉन्ग-टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सतत आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

यूपी बनेगा 'नेशनल लीडर'

गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब इसे निवेश का सशक्त केंद्र बना रहे हैं, जहां वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज, एमएसएमई क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डिफेंस-मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योग तेजी से आकार ले रहे हैं। यह पूरा इकोसिस्टम न केवल सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं, इस मेगा प्रोजेक्ट के संचालन में आते ही उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अग्रणी भूमिका में पहुंच जाएगा और इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% तक हो सकती है। यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य अब इंफ्रास्ट्रक्चर-ड्रिवन ग्रोथ मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि आर्थिक नेतृत्व का माध्यम बन रही हैं।

वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का आधार

उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें गंगा एक्सप्रेसवे एक मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी निवेश को आकर्षित करती है, निवेश से उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योग रोजगार पैदा करते हैं, रोजगार से लोगों की आय बढ़ती है और बढ़ी हुई आय व्यापक आर्थिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे एक 'इकोनॉमिक मल्टीप्लायर' के रूप में कार्य करेगा, जो विकास की इस पूरी श्रृंखला को गति देता हुआ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है।

गर्मियों में श्रमिक और स्वास्थ्य

पसीने की बूंदे, खुशियों का गीत गाती हैं।
वहीं गर्मी में पसीने की धार जोखिम भी लाती हैं।

भारत में गर्मियों का मौसम केवल तापमान में वृद्धि नहीं, बल्कि श्रमिक वर्ग के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर सामने आता है। दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, फैक्ट्री कर्मचारी और यहाँ तक कि कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी-सभी इस मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित होते हैं। वर्तमान समय में बढ़ता निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा व्यवस्था और असंगठित क्षेत्रों में कमजोर होती ट्रेड यूनियन प्रणाली, कर्मचारियों की एकता और संघर्ष करने की शिथिल होती गति ने श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच सीमित आय और सीमित संसाधन में जीवन यापन करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

गर्मी और श्रमिक स्वास्थ्य: एक गंभीर संकट

गर्मी के मौसम में विशेष रूप से वे श्रमिक अधिक प्रभावित होते हैं जो खुले वातावरण या उच्च तापमान वाले कार्यस्थलों पर कार्य करते हैं। प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम:

- **डिहाइड्रेशन (निर्जलीकरण):** अत्यधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी और लवण की कमी
- **हीट एग्जॉशन:** थकान, चक्कर, सिरदर्द, पसीना
- **हीट स्ट्रोक (आपात स्थिति):** शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ना (40C या अधिक)
- **त्वचा संबंधी रोग:** घमौरियाँ, फंगल संक्रमण



- कमजोरी और कुपोषण

चिकित्सालयों में इस मौसम में बुखार, उल्टी-दस्त, कमजोरी और निर्जलीकरण के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है। असंगठित श्रमिकों का अस्थाई निवास केवल उनकी ही नहीं उनके परिवार को भी प्रभावित करता है ।

पोषण और हाइड्रेशनः स्वास्थ्य की कुंजी

गर्मियों में संतुलित आहार और पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन अत्यंत आवश्यक है।

क्या लेंः

- 3–5 लीटर पानी प्रतिदिन (या आवश्यकतानुसार अधिक)
- ओआरएस / नमक-चीनी का घोल
- तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी
- नारियल पानी, छाछ, लस्सी
- हल्का एवं सुपाच्य भोजन
- सत्तू
- नींबू
- ताजी सब्जियां

ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ ।

क्या नहीं लेना चाहिए

- अत्यधिक तैलीय और मसालेदार भोजन
- अत्यधिक चाय, कॉफी और शराब

कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो
- छायादार विश्राम स्थल हो
- कार्य समय में बदलाव (दोपहर में विश्राम)
- सुरक्षात्मक उपकरण (टोपी, हल्के कपड़े)
- नियमित स्वास्थ्य जांच

नीतिगत सुझाव

- हीट वेव एक्शन प्लान पूर्व से तैयार कर उसका क्रियान्वयन
- श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा
- असंगठित क्षेत्र का पंजीकरण
- कर्मचारियों के साथ निश्चित अंतराल पर बैठक
- फीडबैक का आकलन कर कार्यवाही

व्यक्तिगत सावधानियां

- प्यास लगने से पहले पानी पीना
- थोड़ा थोड़ा पानी नियमित रूप से पीते रहना
- सिर को ढककर कार्य करना
- अत्यधिक थकान पर तुरंत विश्राम
- लक्षणों को नजरअंदाज न करना
- खाली पेट ना रहना

गर्मियों में श्रमिकों में डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़ते हैं।

हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति हो सकती है।

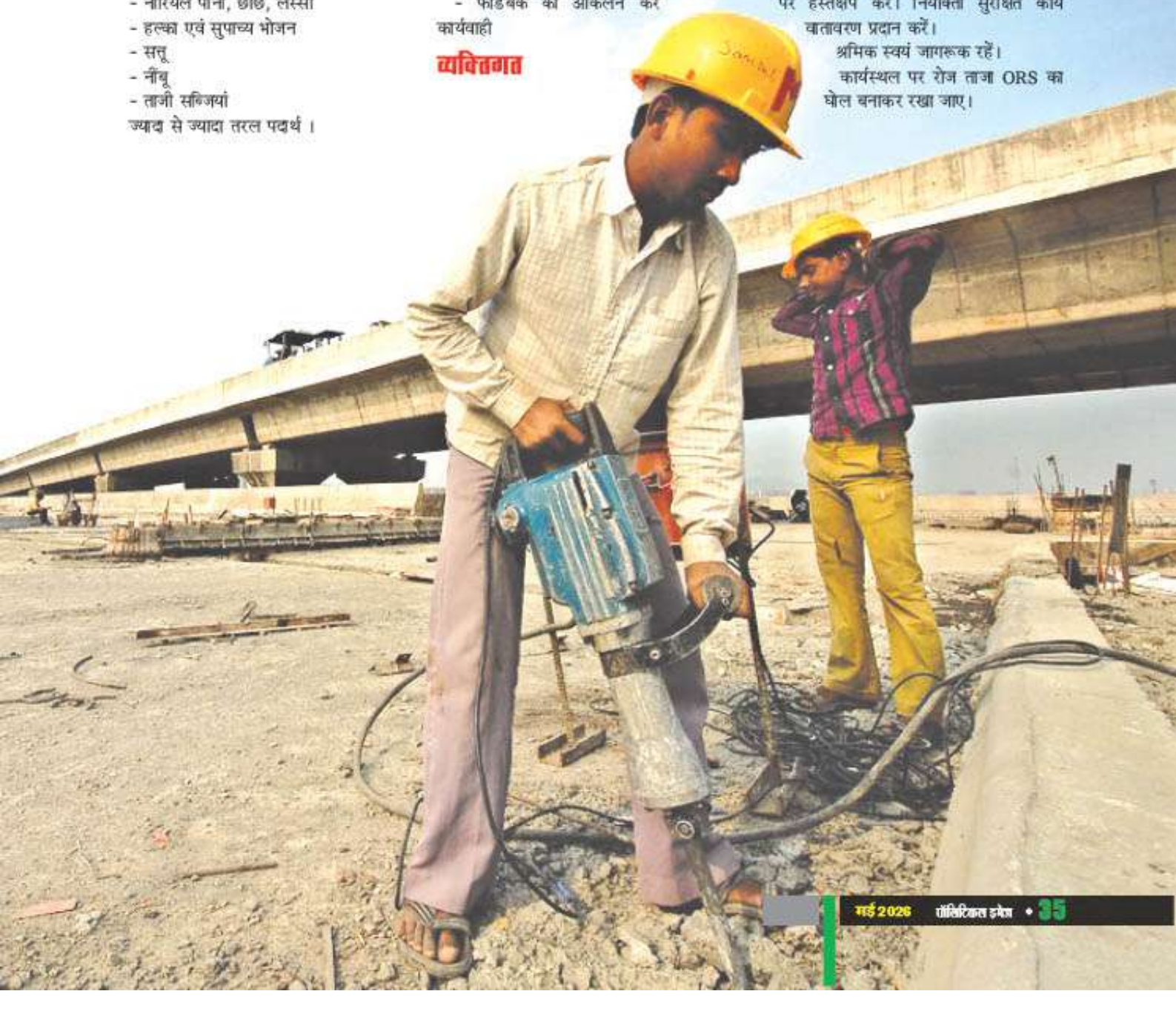
सही आहार और पानी से 70% समस्याओं की रोकथाम संभव है।

किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्काल चिकित्सीय सलाह लें।

श्रमिक हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गर्मियों में उनका स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। आवश्यक है कि- सरकार नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप करे। नियोक्ता सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करें।

श्रमिक स्वयं जागरूक रहें।

कार्यस्थल पर रोज ताजा ORS का घोल बनाकर रखा जाए।



के नाम से भी जाना जाता है. किन्तु वस्तुतः यह उससे विलक्षण है। नाथ सम्प्रदाय में अनेक उपादान अवधूत मत के स्वीकार किये गये हैं।

इसके प्रवर्तक अवधूताचार्य दत्तात्रेय है। 'आदि गुरु दत्तात्रेय और अवधूत दर्शन' (भारतीय संस्कृति और साधना, भास्करी 1. पृ. 191-209) में इस विषय पर विशद प्रकाश डाला गया है। शक्तिसंगमतन्त्र (3/1/148-160) में अवधूतों के सात भेदों का वर्णन मिलता है। वीरावधूत, कौलावधूत, दिव्यावधूत आदि शब्दों का प्रयोग अन्यत्र भी मिलता है। महानिर्वाण तन्त्र में ब्रह्मावधूत, शैवावधूत, वीरावधूत और कुलावधूत का वर्णन उपलब्ध होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ब्रह्मोपासक होने से यति या ब्रह्मावधूत कहते हैं। इस अवस्था में वे लोग गृहस्थाश्रम में रह सकते है अथवा संसार धर्म का त्याग कर संन्यासी हो सकते हैं। विधिपूर्वक पूर्णाभिषिक्त होने पर संन्यासी शैवावधूत कहा जाता है। वीरावधूतों के सिर पर लम्बे और अटपटे केश रहते हैं। ये रुद्राक्ष या महाशंख की माला पहनते हैं। इनके अंगों में भस्म या रक्त चन्दन लिप्त रहता है। प्रायः काला वस्त्र ही पहनते हैं। कुलाचार के अनुसार अभिषिक्त होकर जो साधक गृहस्थाश्रम में रहता है. उसे कुलावधूत कहते हैं। इन शब्दों के अर्थ भी वहाँ प्रदर्शित है। रामानन्द के शिष्यों में भी कुछ अवधूत हुए हैं। वंग देश में तथा अन्यत्र भी इनका निवास है।

ये जाति-भेद को नहीं मानते और पान, भोजन आदि का भी इनका कोई नियम नहीं है। सिर पर बड़े-बड़े बाल, गले में स्फाटिक आदि की माला, कमर में कौपीन लपेटे ये लोग अत्यन्त अपरिष्कृत भाव से रहते है। लोग इन्हें बावला भी कहते हैं। इनका आचरण अत्यन्त उद्धत होता है। बंगाल में स्थान स्थान पर इनके अखाड़े है। अवधूत वर्ण और आश्रम की व्यवस्था से परे रहते हैं। अघोरी भी एक प्रकार का अवधूत ही है। नाथ सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी इनका विवरण मिलता है। गोरक्षसिद्धांत संग्रह (पृ. 15-16) में अवधूत मत को सर्वश्रेष्ठ माना है। अवधूत. साधुओं का एक भेद (प्रकार) है। जो कि अवधूत सम्प्रदाय से होते हैं। यर सम्प्रदाय सबसे पुरानी मानी जाती है। स्वयं भगवान शंकर भी इसी सम्प्रदाय से थे। उसके पश्चात आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय जी भी इसी सम्प्रदाय से हैं। महा कवि जायसी ने लिखा है कि-

खेवरा, सेवरा, पारधी, सिवसाधक, अवधूत।
आसन मारे बैठ, सब पाँच आत्मा भूत ।।

उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा पूर्ण रूप से अवधूत संत है, जिनकी कृपा से सत्यनाथ मठ का जीर्णोधार हो रहा है। पूज्य कपाली बाबा को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक समी परिस्थितियों का सम्यक ज्ञान है। संभवतः आध्यात्मिक एवं जलवायविक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पूज्य महाराज जी प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर लगभग 1 सप्ताह का विशाल



धर्म-संगम सत्यनाथ मठ पर संपन्न करवाते है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता प्रकृति का एक दर्पण है, जिसमें धर्म, कर्म, राजनीति, व्यवसाय, रहन-सहन, विचार विवाद के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी परिवेश प्राकृतिक सत्य से ही नियंत्रित होते है. अर्थात कपाली बाबा कहा करते हैं कि संस्कृति का बहाव जीवन से और जीवन का बहाव प्रकृति से है। क्योंकि-

निगम नेति, शिव पार न पावडिं.....।।

माघ माह के मकर-गति रवि पर गोस्वामी जी ने विशेष बल दिया है। इस समय अवध क्षेत्र के प्रयाग परिक्षेत्र का महत्व अतुलनीय हो जाता है, और ऐसे ही समय में सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाली महराज सत्यनाथ मठ पर एक अवसर प्रदान करते हैं कि जो लोग अपने व्यस्ततम जीवन में प्रयाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे सभी सत्य नाथ मठ पर ही प्रकृति के अनमोल क्षणों का लाभ ले सकते है। ऐसे समय में सत्य नाथ मठ भौगोलिक तथ्यों सहित स्थानिक महत्व को भी पूर्णता प्रदान कर देता है। मकरसंक्रांति महोत्सव के पावन अवसर पर अघोर परम्परा के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अवधूत देशना पर्व आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पर मठ परिसर स्थित अघोर परम्परा के नव नाथों में प्रथम नाथ ब्रह्मा जी के अवतार बाबा सत्यनाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ सहित सभी नव नाथो की प्रतिमा पर मठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्रचण्डेश्वर कपाली बाबा पूजन अर्चन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। यह सुखदाई परिवेश सीमित अवधि तक ही रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। फलता धीरे-धीरे सूर्य मकर वृत्त से बाहर होकर कर्क वृत्त में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की कर्कश किरणें प्रभावी होने लगती है। परिणामतः दक्षिणी गोलार्ध के मकर वृत्त के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध का अनुकूल भौगोलिक पुण्य परिवेश कम होने लगता है अतः सामाजिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक सब विधि मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि माघ महीने में मकर रेखा पर सौर्थिक प्रभाव आदिगंगा गोमती का पावन तट अनेक सांसारिक उपलब्धियों एवं सुखमय जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे समय में सत्यनाथ मठ पर पहुँचकर हम अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बहुत आसानी से अग्रसर कर सकते है। अघोर पीठ बाबा सत्यनाथ मठ आदि गंगा गोमती के पावन तट पर स्थित है। अघोरियों का यह प्रमुख साधना केंद्र अब भी बहुत से रहस्य समेटे हुए है। वर्षों पहले वीरान पड़े इस शैव साधना स्थल पर हरिश्चंद्र घाट काशी के श्मशान पीठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा आकर पुरातात्विक महत्व के इस स्थान के गौरव को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं।

महाभारत काल का स्थल अघोरियों के साधना का प्रमुख स्थल है। शैव साधक और अन्य के लिए यह स्थान किसी भी तीर्थ से कम नहीं है। कादीपुर बाबा सत्यनाथ ने बसाया है, बाबा के बसाये गए गांव या नगर कादीपुर कहलाए। इस स्थान पर अभी भी कादिधारा यन्त्र विद्यमान है. जो आमजन के दर्शनार्थ मंदिर में शिवलिंग और अर्घा के रूप में रखा गया है। इसलिए-

जब यहि भांति बने संयोगू।
अवसि देखिये देखन जोगू ।।
जय महादेव ।

CELEBRATING 73 YEARS OF EXCELLENCE!

SGRRU

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY

DEHRADUN, UTTARAKHAND

UNLOCKING 2X BENEFITS

UPTO

30% SCHOLARSHIP ON TOTAL COURSE FEE

+

ADDITIONAL UPTO 100% SCHOLARSHIPS

ON ELIGIBILITY BASIS

HURRY! SECURE YOUR SEAT NOW

FOR MORE DETAILS CALL

7248889111 | 7248889222 | 7248889112 | 7248889113

VISIT OUR WEBSITE

https://www.sgrru.ac.in

TO REGISTER CLICK

https://admissions.sgrru.ac.in/

यूपी का विधाता अन्नदाता



21%
देश के खाद्यान्न उत्पादन में योगदान

नवनिर्माण के 9 वर्ष

1 देश में नंबर

खाद्यान्न, गन्ना, चीनी, आम दुग्ध, आलू उत्पादन में

3.12 करोड़ किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
₹99 हजार करोड़+
की राशि अंतरित

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान
₹3.15 लाख करोड़+
गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर
₹400 प्रति क्विंटल

बिचौलिया मुक्त बाजार
ई-मंडी में 6.42 करोड़+ पर्चियां

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3.53 करोड़+ किसानों
को क्षतिपूर्ति

किसानों को कार्बन क्रेडिट धनराशि वितरित करने वाला
प्रथम राज्य

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत
86 हजार+
सोलर पंपों की स्थापना

नि:शुल्क बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी हेतु
'उत्तर प्रदेश मंडी भाव'
मोबाइल ऐप

86 लाख+
लघु/सीमांत किसानों का फसल ऋण माफ

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश